शर्मा शर्डअवेब
SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947
70025-06581

E-Paper : www.goodluckpublications.com, • www.vbslive.in

हिंदी दैनिक

गुवाहाटी, नई दिल्ली, शिमला और जम्मू से एकसाथ प्रकाशित

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 10 | अंक : 198 | गुवाहाटी | शुक्रवार, 16 फरवरी, 2024 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

अगले सात दिनों में पीएम देश को देंगे सात एम्स की सौगात — पेज 2

मेघालय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय — पेज 3

पंजाब व दिल्ली की सरकारों ने भड़काया किसान आंदोलन : मुख्यमंत्री मनोहर लाल — पेज 5

भारत ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल हंगरी को सौंपी, खेल मंत्री अनुराग और... — पेज 7

सीएम डॉ शर्मा ने बांटे 840 नियुक्ति पत्र

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मा ने आज राज्य के 15 विभागों के लिए 840 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। गुवाहाटी के पांजाबारी स्थित श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित एक समारोह में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। आज बांटे गए नियुक्ति पत्रों में राज्य सरकार के पर्सनल विभाग के 83, गृह एवं राजनीतिक विभाग के 65, वित्त विभाग के 492, परिवहन विभाग के 2, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 41, श्रम कल्याण विभाग के 7, उत्पाद शुल्क विभाग के 19, सहकारिता विभाग में 6, उद्योग और वाणिज्य और पीई, कौशल, रोजगार और ई विभाग में 7, राजस्व और डीएम विभाग में 10, अल्पसंख्यक विकास एवं कल्याण विभाग में 2, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1, सिंचाई विभाग में 1 और आवास एवं शहरी कार्य विभाग में 97 शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि इस सरकार के कार्यकाल में अब तक राज्य में 93 हजार 557 बेरोजगार युवाओं को नियुक्तियां दी गई थी। आज कुल 840 को नियुक्ति पत्र दिये गये। इस प्रकार कुल संख्या 94 हजार 397 हो गई है।

मैट्रिक परीक्षा आज से

गुवाहाटी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम (सेबा) 16 फरवरी से 4 मार्च, 2024 तक कक्षा 10 (एचएसएलसी) की परीक्षा आयोजित करेगा। शेड्यूल के अनुसार, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं दो पालियों में पेन और पेपर मोड (ऑफलाइन मोड) में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली की अधिकांश पेपर की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच होगी, जबकि कुछ पेपर की परीक्षा दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच होगी। राज्य के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के माध्यम से कहा कि इस साल, एचएस परीक्षा में 876 केंद्रों पर 2,80,216 छात्र शामिल -शेष पृष्ठ दो पर

कांग्रेस का हर विधायक भाजपा में आने को तैयार : मुख्यमंत्री

जोरहाट (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने आज कहा है कि कांग्रेस का हर विधायक भाजपा में आने के लिए तैयार है। लेकिन, जगह के हिसाब से उन्हें धीरे-धीरे करके लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज जोरहाट जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष का अब कोई काम नहीं रहा। जब सरकार सही काम करती है तब विपक्ष की कोई जरूरत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार गलत काम करेगी तो निश्चित ही विपक्ष फिर से मजबूत होकर सामने आ जाएगा। कांग्रेस के दो वरिष्ठ विधायकों द्वारा विधानसभा में भाजपा का समर्थन किए जाने संबंधी सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस से कई लोग भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के विरुद्ध जोरहाट में दर्ज आपराधिक मामले के संदर्भ में पूछे गए एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के सम्मान के लिए ही उन्हें यहां पुलिस के सामने अब तक बुलाया नहीं गया है। उन्हें गवाह के तौर पर तो निश्चित ही बुलाया जाएगा। एक ही दिन में उनके जोरहाट, गुवाहाटी और बिश्वनाथ पुलिस के सामने जाने का कार्यक्रम तय कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के सभी नेता भाजपा में शामिल होना चाह रहे हैं। जो लोग मीडिया के सामने ज्यादा बोलते हैं, वो ही भाजपा में शामिल -शेष पृष्ठ दो पर

आईटी राज्यमंत्री की घोषणा

असम में लगेगा 25000 करोड़ का सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट

गुवाहाटी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं उद्यमिता और जल शक्ति राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को यहां कहा कि असम में जल्द ही करीब 25000 करोड़ रुपे का सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट लगेगा। आईटी राज्यमंत्री ने यह घोषणा यहां डिजिटल इंडिया फ्यूचरस्किल्स शिखर सम्मेलन में की। गुवाहाटी विश्वविद्यालय के बिरिंची कुमार बरुआ ऑडिटोरियम में आयोजित इस शिखर सम्मेलन के दौरान आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह जानकारी दी है। आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि -शेष पृष्ठ दो पर

लाचित की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पीएम को दिया गया निमंत्रण : सीएम

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गुरुवार को कहा कि जोरहाट में महान अहोम जनरल लाचित बरफुकन की 125 फीट से अधिक ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया है। मुख्यमंत्री ने जनरल के *मैदाम* (स्मारक) स्थित कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और जिले के होल्लोंगापार क्षेत्र के लहदोईगढ़ में काम की प्रगति की समीक्षा की। शर्मा ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री कार्यालय से पुष्टि मिलने पर उद्घाटन मार्च के पहले सप्ताह में होगा। शर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि मैं इस मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के साथ चर्चा करूंगा ताकि प्रधानमंत्री के लिए प्रतिमा का उद्घाटन करने के लिए सुविधाजनक तारीख तय की जा सके। उम्मीद है, यह मार्च के पहले सप्ताह में होगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को लाचित बरफुकन सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और परिसर में दो संग्रहालय भी स्थापित किए जाएंगे, एक अहोम -शेष पृष्ठ दो पर

door graph
Premium Quality Hinges
S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

अजित पवार गुट ही असली एनसीपी : महाराष्ट्र के स्पीकर

मुंबई। महाराष्ट्र एनसीपी विधायकों की अपात्रता मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी माना है। यह फैसला अजीत पवार गुट के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। शरद पवार गुट की ओर से अजित पवार समेत सभी 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अजीत पवार गुट के सभी विधायकों को योग्य माना है। इस मामले की सुनवाई करते हुए अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने माना कि अजीत पवार गुट को 41 विधायकों का समर्थन है। इसलिए असली एनसीपी अजीत पवार गुट को ही माना जाएगा। स्पीकर राहुल -शेष पृष्ठ दो पर

त्रिपुरा में देवी सरस्वती की आपत्तिजनक प्रतिमा पर बवाल

अगरतला। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा के दौरान त्रिपुरा के अगरतला में विवाद हो गया। यहां के एक सरकारी कॉलेज में मां सरस्वती की मूर्ति को लेकर जमकर बवाल हुआ। यहां सरस्वती मां की जिस मूर्ति को पूजा के लिए स्थापित किया गया था उसको साड़ी नहीं पहनाई गई थी। इसको लेकर छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामा होते देख कॉलेज प्रशासन ने आनन-फानन में देवी सरस्वती की मूर्ति को साड़ी पहनाई। बाद में विवाद बढ़ने पर विवादित मूर्ति को हटाकर उसे पैक कर दिया गया। यह मामला अगरतला के गवर्नमेंट आर्ट ऐंड क्राफ्ट कॉलेज का है। यहां देवी सरस्वती की मूर्ति को पारंपरिक भारतीय पोशाक साड़ी नहीं पहनाने पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी कॉलेज पहुंच गई। छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। खबरों के मुताबिक, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के समर्थकों का एक समूह बुधवार को अगरतला के निकट लिचुबगन में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में कथित तौर पर जबरन घुस गया। वह कॉलेज में हंगामा करने लगे। दरअसल, कॉलेज में बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा कार्यक्रम का आयोजन था। पूजा कार्यक्रम के लिए कॉलेज परिसर में देवी सरस्वती की मूर्ति लगाई गई थी। यह मूर्ति कथित तौर पर बिना साड़ी के दिखाई दे रही थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया -शेष पृष्ठ दो पर

तृणमूल सांसद मिमी चक्रवर्ती ने छोटी सांसदी

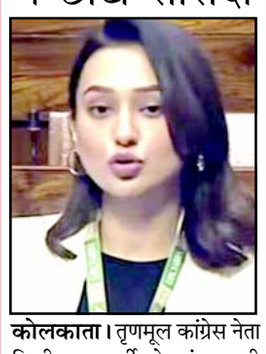

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस नेता मिमी चक्रवर्ती ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने का एलान कर दिया है। वे लोकसभा में पश्चिम बंगाल की जादवपुर सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि, मिमी ने अब तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना इस्तीफा नहीं सौंपा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को अपना त्याग पत्र सौंपा है। बताया जा रहा है कि मिमी स्थनीय स्तर पर पार्टी नेतृत्व से खुश नहीं थीं। इस वजह से उन्होंने यह कदम उठाया है। मिमी चक्रवर्ती ने इस्तीफा देने को लेकर कहा कि राजनीति मेरे लिए नहीं है, यहां अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आपको उसका प्रचार करना होता है। राजनीति के साथ-साथ मैं एक अभिनेत्री के रूप में भी कार्य -शेष पृष्ठ दो पर

सुप्रभात
योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बढ़ा कठिन होता है।
- आचार्य चाणक्य

न्यूज गैलरी

धमकी : दिल्ली एचसी समेत सभी निचली अदालतों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध

नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ई-मेल के जरिए मिली धमकी के बाद हाई कोर्ट समेत दिल्ली की सभी निचली अदालतों में सुरक्षा के प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समेत कुछ निचली अदालतों की बार एसोसिएशन -शेष पृष्ठ दो पर

एसकेएम का भारत बंद आज

नई दिल्ली (हि.स.)। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को किसानों और श्रमिकों के मुद्दों को लेकर ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है। एसकेएम ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि वह चाहते हैं कि किसानों को सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी दी जाए। इसके साथ ही पंजाब सीमा पर किसानों पर पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। एसकेएम के एक पदाधिकारी ने कहा कि किसान चाहते हैं कि सरकार ने जो वादे आंदोलन के समय किए थे, उन्हें पूरा करे। उधर, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की मांग है कि सभी मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26,000 हजार रुपे प्रति माह किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने शुक्रवार को ग्रामीण बंद को लेकर गाइडलाइन जारी है। एसकेएम देश भर के लोगों से कॉर्पोरेट लूट को खत्म करने, कृषि बचाने -शेष पृष्ठ दो पर

असम प्रदेश कांग्रेस ने बंद का किया समर्थन

गुवाहाटी (हि.स.)। भारत के किसानों के कई संगठनों द्वारा विभिन्न ज्वलंत मुद्दों, विशेषकर एमएसपी गारंटी, बेरोजगारी की समस्याओं, केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों और असम की छह जनजातियों के गैर-आदिवासीकरण, चाय श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने के वादे को पूरा नहीं करने, असम समझौते की अनदेखी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से समाज में भाईचारा, शांति और सद्भाव को नष्ट करने की समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, -शेष पृष्ठ दो पर

म्यांमार के 330 जवान बांग्लादेश से लौटे स्वदेश

ढाका (हि.स.)। बांग्लादेश में शरण लिए म्यांमार के 330 सीमा रक्षकों और सेना के जवानों को वापस भेजने की प्रक्रिया आज (गुरुवार) सुबह शुरू हो गई। इससे पहले दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियों के बीच बैठक में इस मसले पर चर्चा हुई। ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के जनसंपर्क अधिकारी शरीफुल इस्लाम के हवाले से यह जानकारी दी गई है। शरीफुल इस्लाम ने कहा कि बैठक में बॉर्डर गार्ड -शेष पृष्ठ दो पर

हेमंत सोरेन को 22 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को एक विशेष पीएमएलए अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में थे। पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि हेमंत सोरेन को आज विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया और उन्हें 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हम उनके लिए जमानत याचिका दायर करेंगे। सोरेन को अदालत से रांची की -शेष पृष्ठ दो पर

कैंसर की वैक्सीन बनाने के करीब पहुंचा रूस : पुतिन

मास्को (हि.स.)। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को दावा किया कि रूसी वैज्ञानिक कैंसर की वैक्सीन बनाने के करीब पहुंच चुके हैं। पुतिन ने दावा किया कि वैज्ञानिक जल्द ही इसे मरीजों के लिए उपलब्ध कराएंगे। पुतिन ने कहा कि हम कैंसर वैक्सीन और नई पीढ़ी की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत करने वाली दवाओं के निर्माण के बहुत करीब आ गए हैं। पुतिन ने उम्मीद जताई कि जल्द ही उनका प्रभावी ढंग से चिकित्सा के रूप में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने मास्को में भविष्य की तकनीकों पर आयोजित कार्यक्रम में ये बातें कहीं। पुतिन ने यह नहीं बताया कि प्रस्तावित टीके किस प्रकार के कैंसर को लक्षित -शेष पृष्ठ दो पर

प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर से की मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा

नई दिल्ली (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री का आज दोहा में औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर सार्थक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने अमीर को भारत आने का निमंत्रण दिया और साथ ही आठ भारतीयों की रिहाई के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रधानमंत्री ने मुलाकात से जुड़ी जानकारी एक्स पर साझा की और बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापार और वाणिज्य, ऊर्जा, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत-कतर संबंधों को और मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि हमने भारत-कतर संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देश भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए भी तत्पर हैं, जिससे हमारे ग्रह -शेष पृष्ठ दो पर

महाभारत के कृष्ण के घर में महाभारत

भोपाल। प्रतिष्ठित धारावाहिक महाभारत में भगवान कृष्ण के किरदार के लिए विशेष रूप से पहचाने जाने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने हाल ही में अपनी पत्नी स्मिता भारद्वाज के खिलाफ एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। उन्हें लंबे समय तक अपनी जुड़वां बेटियों से मिलने से रोकने के आरोपों के कारण अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत की है। नीतीश ने स्मिता की हरकतों पर अपनी परेशानी व्यक्त करते हुए दावा किया कि उन्हें उनकी बेटियों तक पहुंचने से रोका जा रहा है। एक्टर नीतीश ने कथित तौर पर आरोप लगाए कि अपने बच्चों से मिलने से बचाने के लिए उनके -शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivling, Nandi etc.
ARTCLE WORLD,
S-29, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01,
Ph. : 94350-48866,
94018-06952

अगले सात दिनों में पीएम देश को देंगे सात एम्स की सौगात

नई दिल्ली (हि.स.)। आगामी एक हफ्ते में देश को सात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की सौगात मिलने वाली है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ 20 फरवरी को वे जम्मू एम्स का उद्घाटन करेंगे और 25 फरवरी को देश को पांच एम्स अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि पिछले 60 सालों में देश में सिर्फ 6 एम्स थे लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में एक हफ्ते में सात एम्स देश को समर्पित किया जा रहा है। 10 हजार करोड़ की लागत से तैयार सभी सात एम्स देश के स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूती देंगे और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। गुरुवार को मीडिया से बातचीत में डॉ. मांडविया ने बताया कि 25 फरवरी को देश में पांच एम्स राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जिसमें राजकोट एम्स (गुजरात), मंगलगीरी एम्स (आंध्रप्रदेश), रायबरेली एम्स (उत्तर प्रदेश), कल्याणी (पश्चिम बंगाल) एम्स और भटिंडा एम्स शामिल है। इन सभी एम्स को विकसित करने पर केंद्र सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने बताया कि देश के कई एम्स में पिछले छह महीनों में 29, हजार फैकल्टी की नियुक्तियां की गई हैं। इन एम्स के शुरुआत से देश में स्वास्थ्य सेवा और मजबूत होगी और लाखों लोगों को इससे लाभ मिलेगा। 203 एकड़ में बनाए जाने वाले रेवाड़ी एम्स में 750 बिस्तर, 30 ट्रामा बेड, 75 आईसीयू बेड, 16 ऑपरेशन थियेटर, 15 सुपर स्पेशलिटी विभाग, सीटी स्कैन, एमआरआई, लैब की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें शैक्षणिक भवन भी बनाए जाएंगे, जिसमें मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, 500 सीट वाला ऑडिटोरियम, आयुष ब्लॉक - 30 बिस्तर होंगे। इसके साथ 150 लोगों के लिए रात्रि आश्रय भी होगा। इसके साथ आवासीय इकाइयां, छात्रावास भी बनाए जाएंगे। लगभग 1646 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस एम्स से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ होगा।

राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए बजटीय प्रावधान बढ़ा कर किया गया 1200 करोड़ रुपए

नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय आयुष मंत्री ने सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 तक एनएएम के एक घटक के रूप में राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से आयुष मंत्रालय ने 12,500 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) के संचालन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए बजटीय प्रावधान 800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए कर दी गई है। पटना में गुरुवार को आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में भाग लेते हुए सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि योग और आयुष पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अपने संबंधित राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने राज्यों से आयुष सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर जोर देने की भी अपील की।

भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन कल से 11 हजार से अधिक डेलिगेट्स लेंगे भाग

नई दिल्ली (हि.स.)। आगामी लोकसभा चुनाव में 400 से अधिक सीट जीतने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 17-18 फरवरी को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन करेगी। भारत मंडपम में आयोजित होने वाली इस बैठक में देश से 11,500 से अधिक डेलिगेट्स भाग ले रहे हैं। भाजपा मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 से पार के लक्ष्य को साधने के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। इस अधिवेशन का उद्घाटन 17 फरवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समापन भाषण देंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दो दिवसीय बैठक आगामी चुनावों पर केंद्रित होगी। इसके साथ ही *विकसित भारत* की अवधारणा को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है। इस बैठक में दो प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इसके साथ विस्तारकों की बैठक भी आयोजित की जाएगी।

सत्ता पक्ष के उगाही का जरिया रहा इलेक्टोरल बॉन्ड : कांग्रेस

नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलेक्टोरल (चुनावी) बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिए जाने पर कांग्रेस ने खुशी जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर उगाही का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि भाजपा को *इलेक्टोरल बॉन्ड* से 5200 करोड़ रुपे मिले हैं। ये रुपे किसने दिए, यह बात देश को बताना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि एसबीआई तमाम जानकारी को सार्वजनिक पटल पर रखे, जिससे जनता को मालूम पड़े कि किसने कितना पैसा दिया। खेड़ा ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मोदी सरकार *मनी बिल* के तौर पर लाई थी, ताकि राज्यसभा में इसपर चर्चा न हो, यह सीधा पारित हो जाए। ऐसे में हमें डर है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी न हो जाए और मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बच जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें सीधे-सीधे प्रधानमंत्री शामिल हैं। देश पर इलेक्टोरल बॉन्ड को थोपा गया जबकि चुनाव आयोग, वित्त मंत्रालय और लॉ मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने विरोध किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोदी सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के सर्वसम्मत फैसले का स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चुनावी बॉन्ड योजना संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ ही भारत के संविधान का भी उल्लंघन कर रही है। वर्ष 2017 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था, तब से कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रही है। यह प्रक्रिया अपारदर्शी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है।

पुलिस के हथियार लूटने के आरोप में छह गिरफ्तार

इंफाल (हिंस)। मणिपुर पुलिस का हथियार लूटने के छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से लूटे गए हथियार बरामद किए गए हैं। मणिपुर पुलिस ने आज बताया कि विगत 13 फरवरी की रात को अनियंत्रित भीड़ द्वारा 5वीं आईआरबी, चिंगारेल, इंफाल पूर्व में हथियार लूटने की घटना के संबंध में मणिपुर पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

आग में जलकर एक महिला की मौत, पांच घर जलकर राख

दरंग (हिंस)। दरंग जिले के दलगांव अंतर्गत बरुवाझाड़ गांव में बीती रात भीषण आग लग गई। आग में बुरी तरह से झुलकर एक महिला की मौत हो गई। वहीं पांच परिवारों के घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। पुलिस सूत्रों ने आज बताया है कि मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों ने संदेह जताया है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग की वजह से लाखों रुपए के दस्तावेज और सामग्री जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही आनन-फानन में फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग में मालेका बेगम (45) नामक महिला की बुरी तरह से झुलने के चलते मौत हो गई।

मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे ट्रैक्टर हाइट गार्डर से टकराई, तीन की मौत

अररिया (हि.स.)। बिहार में अररिया नगर थाना क्षेत्र के दियारी पंचायत के मजगामा वार्ड संख्या तीन के पास गुरुवार की देर शाम ट्रैक्टर से मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे लोगों की सड़क पर लगे हाइट गाडर से टकरा जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। मामला नगर थाना क्षेत्र के दीयारी पंचायत के मजगामा वार्ड नंबर तीन की है। दरअसल यह सभी सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन करने गांव के ही करीब नदी किनारे गए थे और वहां से प्रतिमा विसर्जन कर जब सभी लौट रहे थे तभी ये हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर चालक को सड़क पर लगा हाइट गाडर नहीं दिखा,जिसके कारण ट्रेक्टर उससे टकरा गई और इतना बड़ा हादसा हुआ। टक्कर में करीब एक दर्जन लोग वहां पर चोटिल हो गए। जिनमें तीन-चार लोगों की स्थिति काफी नाजुक थी। तब स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर वहां से सभी घायलों को सदर अस्पताल ले आई। जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अली हसन ने घायलों की जांच की जिनमें तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। वही 4 की स्थिति गंभीर देते हुए उसे फौरन हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं बाकी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है।

सीएम सावंत ने कैबिनेट के साथ किए रामलला के दर्शन

अयोध्या (हि.स.)। राम मन्दिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से अयोध्या में लगातार श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। देश विदेश से रामभक्त रामलला का दर्शन पूजन करने चले आ रहे हैं। दर्शन के क्रम में विभिन्न राज्यों की पूरी कैबिनेट भी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रही है। इससे पहले यूपी व अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट भी रामलला का दर्शन कर चुकी है। इसी क्रम में गुरुवार को गोवा सरकार की कैबिनेट सीएम प्रमोद सावंत के नेतृत्व में रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंची। इस दल में कुल 51 सदस्य शामिल रहे। गोवा कैबिनेट के सभी मंत्री व विधायक राजर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या पहुंचे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोवा प्रदेश से आए अतिथियों की सुरक्षा व्यवस्था के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए थे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में वे दो बार कारसेवा कर चुके हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री भी साथ रहे। उन्होंने कहा कि आज पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या आया हूं यह मेरा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को पूरे गोवा के गांव अयोध्या बन चुके थे। पूरा प्रदेश राममय था। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि राम मंदिर बनने की वजह से हम लोग अयोध्या आ पाए हैं। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम योगी और राम मंदिर ट्रस्ट का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सीएम ने कहा कि गोवा को मुख्यमंत्री दर्शन योजना के तहत अयोध्या से जोड़ा जाएगा, जिससे वहां के लोग रामलला का दर्शन आसानी के साथ कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने यदि भूमि दी तो वह अयोध्या में गोवा का भवन जरूर बनना चाहेंगे। कहा अब तो यहां आना-जाना लगा ही रहेगा।

पृष्ठ एक का शेष

मैट्रिक परीक्षा आज...

होंगे। बोर्ड द्वारा सभी छात्रों के लिए 2024 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड जोनों में भेजे गए और फिर संबंधित स्कूलों को वितरित किए गए, जो छात्रों को उन्हें वितरित करने के लिए जिम्मेदार थे। एडमिट कार्ड में छात्र का रोल नंबर, परीक्षा का नाम और कोड, पंजीकरण संख्या, परीक्षा केंद्र और अन्य प्रासंगिक जानकारी जैसे महत्वपूर्ण विवरण होंगे। यह प्रवेश पत्र परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज होगा, क्योंकि इसके बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा लिखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछले साल, कक्षा 10 की परीक्षा में बैठने वाले 4,15,324 छात्रों में से 3,01,880 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। बोर्ड ने कुल मिलाकर 72.69 प्रतिशत उत्तीर्ण प्रतिशत दर्ज किया।

कांग्रेस का हर विधायक ...

होना चाहते हैं, लेकिन भाजपा में सभी के लिए ज्यादा जगह नहीं है। वे सभी के लिए जगह बना रहे हैं, एक-दो करके कांग्रेस नेताओं को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो कैमरे और प्रेस के सामने तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल हो जाते हैं या भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कोई किसी न किसी समय भाजपा में आएगा।

असम में लगेगा 25000...

असम सरकार और टाटा समूह के साथ साझेदारी में एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। हम जल्द ही सभी प्रकार की मंजूरी प्राप्त कर लेंगे और इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट को सौंप देंगे। सेमीकंडक्टर की दुनिया में प्रवेश करने के इच्छुक युवा भारतीयों को अब अपना राज्य छोड़ने या दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। आईटी राज्यमंत्री ने असम में सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्लांट लगाये जाने का श्रेय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व को दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था में पिछले एक दशक के दौरान काफी प्रगति हुई है और कभी दुनिया के पांच सबसे बदहाल अर्थव्यवस्थाओं में शुमार भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बढ़ी आर्थिक ताकत है। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है और देश में युवाओं के लिए अवसरों की अपार संभावनाएं हैं, विशेष रूप से उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत शेष दुनिया के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। उन्होंने कहा कि फ्यूचरस्किल्स के माध्यम से, हम देश के युवाओं को यह बताना चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण आने वाले वर्षों में उनके लिए अनेक अवसरों पैदा होंगे। विद्यार्थियों को एआई, साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में खुद को सशक्त बनाने और कौशल से लैस करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में दुनिया की अग्रणी कंपनियां, जिनमें एनवीआईडीआईए, इंटेल, एएमडी, एचसीएल, विप्रो और आईबीएम शामिल हैं, आज यहां गुवाहाटी में मौजूद हैं। वे सभी एक ही संदेश साझा करते हैं कि नौकरी के जबरदस्त अवसर हैं, लेकिन इसके लिए कौशल बहुत जरूरी है।

लाचित की प्रतिमा...

युग पर और दूसरा उस काल की कलाकृतियों वाला एक युद्ध संग्रहालय। उन्होंने कहा कि यह असम के लिए बड़ा सम्मान होगा अगर प्रधानमंत्री लाचित बरफुकन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और बहादुर अहोम जनरल को श्रद्धांजलि देंगे। असम के इतिहास में बरफुकन को 1671 में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौसैनिक युद्ध में *सरायघाट की लड़ाई* में मुगल सेना को विफल करने के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त, पीएम से शिवसागर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत निर्मित 5.5 लाख घरों के लिए *गृह प्रवेश* (गृह प्रवेश) समारोह में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। शर्मा ने प्रधान मंत्री की बैठक के लिए प्रस्तावित स्थल मेलेंग मेटेली पोथार का भी निरीक्षण किया और तैयारियों का आकलन किया, जिसमें सुचारू सार्वजनिक पहुंच, सुरक्षा व्यवस्था, पीने के पानी जैसी सुविधाओं का प्रावधान और उपस्थित लोगों के लिए परिवहन सुनिश्चित करना शामिल है।

अजित पवार गुट...

नार्वेकर ने कहा कि शरद पवार गुट की यह दलील खारिज की जाती है कि विधायी बहुमत के आधार पर मामले का फैसला नहीं किया जा सकता। अजित पवार के पास 41 विधायकों का विधायी बहुमत है। यह निर्विवाद है। मेरा मानना है कि वास्तविक राजनीतिक दल को विधायक दल के बहुमत से परिभाषित किया जा सकता है। अजित पवार के पास विधायी बहुमत है। मेरा मानना है कि अजित पवार ही असली राजनीतिक पार्टी हैं। एनसीपी के विधायकों की अयोग्यता के मामले में महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने गुरुवार को फैसला सुनाया। गुरुवार शाम अपने फैसले में उन्होंने सभी विधायकों को योग्य ठहराया और अयोग्या के मामले की सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है। उन्होंने अजित गुट को ही असली एनसीपी भी घोषित किया। स्पीकर ने कहा कि अजित पवार के पास 41 विधायकों का समर्थन हैं। इससे पहले 6 फरवरी को भी चुनाव आयोग के फैसले में शरद पवार को ही बड़ा झटका लगा था। कारण था कि चुनाव आयोग ने भी अजित गुट को ही असली एनसीपी करार दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि तमाम सबूतों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग का कहना था कि अजित पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने का अधिकार है। हालांकि आयोग ने शरद पवार को नई पार्टी के गठन के लिए तीन नाम देने को कहा था।

त्रिपुरा में देवी सरस्वती...

पर वायरल हो गया। वीडियो हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों को मिला। उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कॉलेज में हंगामा कर दिया। कॉलेज में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। हंगामा होते देख कॉलेज प्रशासन ने मूर्ति को साड़ी पहनाई। विवाद जब भी नहीं थमा तो उस मूर्ति को हटाकर उसे प्लास्टिक के कवर से ढक दिया। बाद में यहां देवी सरस्वती की नई मूर्ति लगवा दी गई। इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने कहा कि हमारा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने का इरादा नहीं था। इस मामले में बजरंग दल की त्रिपुरा इकाई के समन्वयक तूतन दास ने कहा कि सोशल मीडिया पर बिना पारंपरिक साड़ी के मां सरस्वती की प्रतिमा का वीडियो प्रसारित हो रहा था। हम पूजा शुरू होने से पहले तुरंत कॉलेज पहुंचे और आयोजकों से प्रतिमा को साड़ी पहनाने के लिए मजबूर किया। विहिप के सहायक संयोजक (अभियान) सौरभ दास ने भी विद्यार्थियों की इस हरकत की निंदा की। उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के विद्यार्थियों द्वारा देवी सरस्वती के प्रति प्रदर्शित निरादर की कड़ी निंदा करते हैं। विहिप, हिंदू देवी-देवताओं के प्रति किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी।

एसकेएम का भारत ...

और भारत को बचाने के ऐतिहासिक संघर्ष को सफल बनाने के लिए समर्थन और सहयोग करने की अपील की है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ग्रामीण बंद रहेगा। गांव सभी कृषि गतिविधियों, मनरेगा कार्यों, ग्रामीण कार्यों के लिए बंद रहेगा। कोई भी किसान, कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक काम पर नहीं आएगा। सब्जियों, अन्य फसलों की आपूर्ति और खरीद निलंबित रहेगी। गांव की सभी दुकानें, अनाज मंडियां, सब्जी मंडियां, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, ग्रामीण औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के संस्थान और निजी क्षेत्र के उद्यमों को बंद रखने का अनुरोध किया जाता है। शहरों की दुकानें और प्रतिष्ठान हड़ताल के घंटों के दौरान बंद रहते हैं। सामान्य सार्वजनिक और निजी परिवहन सड़कों से दूर रहेंगे। एंबुलेंस, मृत्यु, विवाह, चिकित्सा दुकानें, समाचार पत्र आपूर्ति, बोर्ड परीक्षा, यात्रियों की हवाई अड्डे तक आपातकालीन सेवाओं के लिए मार्ग सुनिश्चित करें। किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के दौरान विशाल चक्का जाम, रास्ता रोको, रोड धरना में शामिल होंगे। किसानों, श्रमिकों और परिवार के सदस्यों के साथ शामिल होने के लिए गांव, तहसील और जिला केंद्रों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद विशाल प्रदर्शन और सार्वजनिक बैठकें हुईं।

असम प्रदेश कांग्रेस...

आनुसांगिक संगठनों, विभिन्न प्रकोष्ठों और विभागों सहित सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से शुक्रवार को बुलाए गए भारत बंद कक समर्थन और सहयोग देने का आग्रह किया है।

म्यांमार के 330 ...

बांग्लादेश के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमां सिद्दीकी के नेतृत्व में म्यांमार के बॉर्डर गार्ड पुलिस के अधिकारियों ने बैठक की। उन्होंने कहा कि म्यांमार के जवानों को सौंपने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नाइखोंगचारी में घुमदम और टेकनाफ में हनीला से म्यांमार के बॉर्डर गार्ड पुलिस के सदस्यों को इनानी में नौसेना जेटी घाट के पास एक क्षेत्र में लाया गया है। यह सदस्य चार से सात फरवरी के बीच बांग्लादेश आए थे।

हेमंत सोरेन को ...

बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह ईडी की हिरासत में हैं। अदालत ने शुरू में पांच दिनों की ईडी हिरासत दी, जिसे बाद में कुल सात दिनों के लिए दो बार बढ़ाया गया। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनशोधन जांच में घोर असहयोगपूर्ण रवैया दिखा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि सोरेन कथित तौर पर अपने द्वारा अर्जित की गई भूमि के बारे में जानकारी देने के इच्छुक नहीं हैं। ईडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के 48 वर्षीय नेता को न्यायाधीश राजीव रंजन की विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया, जिसने उनकी ईडी हिरासत तीन दिन के लिए और बढ़ा दी। एजेंसी ने पूर्व में आरोप लगाया था कि जांच शुरू होने के बाद जमीन का उक्त टुकड़ा राजकुमार पाहन नाम के एक व्यक्ति को वापस कर दिया गया था। इसने कहा कि सोरेन सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपने से जुड़ी संपत्तियों के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार नहीं हैं और इसलिए उनकी ईडी हिरासत बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। एजेंसी ने कहा कि मामले में सात फरवरी को तलाशी ली गई और नए सबूत सामने आए हैं।

तृणमूल सांसद मिमी...

करती हूं, मेरा दायित्व दोनों तरफ एक समान बनता है, अगर कोई राजनीति में आता है तो आप काम करें या न करें आपको भला-बुरा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे जो परेशानी है उसे लेकर मैंने ममता बनर्जी से बात की है। जिस पार्टी ने मुझे आगे आने का मौका दिया, मैं अपने इस्तीफे की जानकारी उन्हें पहले देना चाहती हूं। 2022 में भी मैंने एक बार अपने सांसद पद से इस्तीफे को लेकर दीदी से बात की थी, तब उन्होंने इसे नामंजूर कर दिया था। दीदी जो कहेंगी उसके बाद मैं आगे की प्रक्रिया को पूरा करूंगी।

कैंसर की वैक्सीन ...

करेंगे और न ही उन्होंने बताया कि यह कैसे काम करेगा। कई देश और कंपनियां कैंसर के टीकों पर काम कर रही हैं। पिछले साल ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी स्थित बायोएनटेक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कैंसर उपचार प्रदान करने के लिए परीक्षण शुरू करेगा। जिसका लक्ष्य 2030 तक 10,000 रोगियों तक पहुंचना है। फार्मास्युटिकल कंपनियां मार्डना और मर्क एंड कंपनी एक प्रयोगात्मक कैंसर वैक्सीन विकसित कर रही हैं, जो एक मध्य चरण अध्ययन में तीन साल के उपचार के बाद मेलेनोमा (सबसे घातक त्वचा कैंसर) से मृत्यु की संभावना को आधा कर देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वर्तमान में छह लाइसेंस प्राप्त टीके हैं जो कई तरह के कैंसरों का कारण बनने वाले मानव पेपिलोमाविरस (एचपीवी) के उपचार के लिए हैं, जिनमें सर्वाइकल कैंसर भी शामिल है। साथ ही हेपेटाइटिस बी (एचबीएस) के खिलाफ टीके भी हैं, जो लीवर कैंसर का कारण बनता है।

प्रधानमंत्री ने कतर...

को लाभ होगा। उधर, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री की कतर यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रणनीतिक निवेश और रणनीतिक साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने अल दहरा कंपनी के आठ भारतीय नागरिकों की रिहाई के फैसले पर धन्यवाद देते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर को भारत आने का निमंत्रण दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी दृष्टिकोण का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने कतर में भारतीय समुदाय के कल्याण कार्यों के लिए अमीर को धन्यवाद दिया।

महाभारत के कृष्ण...

स्कूल ही बदल दिए गए। इसके अलावा, नीतीश ने इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए भोपाल पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कर कानूनी सहारा लिया है। नीतीश ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाए हैं कि वह अपनी बेटियों के बारे में नहीं बता रही है कि दोनों कहां हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि उनकी पत्नी बच्चों को नीतीश के खिलाफ भड़का रही है। गौरतलब है कि मुंबई फैमिली कोर्ट ने स्मिता को आदेश दिया है कि वह नीतीश को उनके साथ रहने के बावजूद अपनी बेटियों से मिलने की इजाजत दें। वहीं, नीतीश ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्मिता ने मुझे पिछले चार सालों से अपनी दोनों बेटियों ने नहीं मिलने दिया है। मेरी पत्नी ने पहले भोपाल और अब ऊटी के बोर्डिंग स्कूल से बेटियों का निकालकर किसी दूसरी जगह पढ़ने के लिए भेज दिया है। मध्य प्रदेश कैडर में 1992 बैच की आईएएस अधिकारी स्मिता भारद्वाज वर्तमान में खेल और युवा कल्याण के साथ-साथ खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों में अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद पर तैनात हैं। दोनों के बीच का विवाद, साल 2019 में तलाक के आवेदन के बाद सबके सामने आया था। नीतीश ने सितंबर 2021 में अपनी बेटियों से बात न कर पाने और न मिल पाने के बाद शिकायत दर्ज करवाई थी।

धमकी : दिल्ली एचसी ...

ने वकीलों को संदेश भेजकर सुरक्षा जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है। इसी तरह कड़कड़डूमा कोर्ट के बार एसोसिएशन शाहदरा बार एसोसिएशन के सचिव रमन शर्मा ने भी संदेश भेजा है और सभी वकीलों से सुरक्षा जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है। साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील कामोद कुमार यादव ने भी पुष्टि करते हुए कहा है कि बार एसोसिएशन ने सुरक्षा जांच में सहयोग करने को कहा है।

मेघालय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

शिलांग (हिंस)। मेघालय कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बताया कि मेघालय राज्य निवेश संवर्धन और सुविधा विधेयक (एमएसआईपीएफ), 2024 को मंजूरी दे दी गई। इससे मेघालय प्राधिकरण के निर्माण का रास्ता साफ हो गया, जो राज्य की मौजूदा सिंगल विंडो एजेंसी की जगह लेगा। राज्य में लंबे समय से प्रचलित सिंगल विंडो एजेंसी में कुछ संशोधनों और सुधारों की आवश्यकता थी और नया विधेयक एक एकीकृत प्रणाली बनाएगा, जहां विभिन्न विभागों को शामिल करने वाले पोर्टलों के माध्यम से एकीकृत आवेदन किए जाएंगे। जिसमें सभी

निवेशों और प्रस्तावों की ट्रैकिंग प्रणाली होगी। प्रस्तावों की मात्रा के आधार पर निवेश का वर्गीकरण भी होगा। कैबिनेट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश सचिवीय सहायता और घरेलू सहायता नियम, 2013 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसे आखिरी बार 2016 में संशोधित किया गया था। न्यायपालिका के अनुरोध के आधार पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के लिए सचिवीय सहायता और अन्य वित्तीय सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि को बढ़ाने के लिए नियमों में संशोधन किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) द्वारा अनुशंसित भत्तों को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जिसमें कहा गया है कि राज्य में न्यायिक मजिस्ट्रेटों तथा न्यायिक अधिकारियों को दिए जाने वाले लाभ राष्ट्रीय स्तर पर होने चाहिए। आगामी विधानसभा सत्र से पहले विभिन्न अध्यादेशों को विधेयक के रूप में सदन में रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें कैप्टन विलियमसन संगमा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 में संशोधन तथा मेघालय की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2024 शामिल हैं।

नुमलीगढ़ रिफाइनरी वर्कर्स यूनियन ने किया विरोध-प्रदर्शन

गोलाघाट (हिंस)। नुमलीगढ़ रिफाइनरी वर्कर्स यूनियन ने आज अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ नुमलीगढ़ रिफाइनरी के मुख्य प्रवेश द्वार पर बैठक के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों और मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की मांग की गई। बैठक में किसानों और मजदूरों के लिए उचित मजदूरी सुनिश्चित करने, दवाइयों, खाद्य और कृषि उत्पादों को जीएसटी मुक्त करने, पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस पर उत्पाद शुल्क में कमी करने, भाजपा सरकार की सांप्रदायिक राजनीति को रोकने की मांग करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। आज सुबह नुमलीगढ़ रिफाइनरी वर्कर्स यूनियन ने केंद्र सरकार को मांगों को लागू करने की चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह के और भी विरोध प्रदर्शन किये जाएंगे।

डीएमसीएच से इलाजरत सजायाफ्ता कैदी फरार

धुबड़ी (हिंस)। मादक पदार्थों की तस्करी का सजायाफ्ता मुजरिम धुबड़ी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल (डीएमसीएच) से फरार हो गया है। फरार कैदी की पहचान गुलजार उद्दीन अहमद उर्फ राजू के रूप में हुई है। दस साल के कठोर कारावास की सजा पाने वाले राजू को बीमारी के कारण 6 फरवरी को धुबड़ी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उल्लेखनीय है कि गत 3 जनवरी को धुबड़ी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद बुरहानुर रहमान की अदालत ने दो भाइयों गुलजार उद्दीन अहमद उर्फ राजू और गफूर उद्दीन अहमद उर्फ राकेश को दोषी ठहराते हुए उन्हें दस साल के कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानुर रहमान ने जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई। आरोपी धुबड़ी के आईजी रोड स्थित वार्ड नंबर-13 के रहने वाले हैं। जिला जेल अधीक्षक प्रशांत राजवंशी ने धुबड़ी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल से गुलजार उद्दीन अहमद के भागने की

पुष्टि की है। इस दौरान अपर लोक अभियोजक दिनेश चौधरी ने बताया कि 12 जुलाई, 2022 को गुलजार उद्दीन अहमद और गफूर उद्दीन अहमद को पुलिस अवर निरीक्षक चंदन राउत ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप फेंसिडिल के साथ गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ अगले दिन 13 जुलाई 2022 आरोप संख्या 262/2022 के तहत धुबड़ी सदर पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 22 (सी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद, मामले की जांच पुलिस अधिकारी, सब-इंस्पेक्टर (पी) बहारुल इस्लाम ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

दूसरा बोड़ोलैंड स्पोर्ट्स मीट- 2024 आरंभ

कोकराझाड़ (हिंस)। दूसरा बोड़ोलैंड स्पोर्ट्स मीट- 2024 आज से कोकराझाड़ में शुरू हुआ। बोड़ोलैंड स्पोर्ट्स मीट- 2024 आज से खेल और युवा कल्याण निदेशालय, बोड़ोलैंड टेरिटोरिल रिजन (बीटीआर) की पहल के तहत आयोजित किया जा रहा है। बोड़ोलैंड स्पोर्ट्स मीट- 2024 आज से तीन दिवसीय कार्यक्रमों के साथ कोकराझाड़ में भारतीय खेल प्राधिकरण में आयोजित किया जा रहा है। बीटीआर के पांच जिलों के लगभग 1600 खिलाड़ी इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। बोड़ोलैंड स्पोर्ट्स मीट- 2024 के दौरान मुख्य रूप से तीरंदाजी, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही बोड़ो समाज के स्थानीय खेल भी आयोजित किये जाएंगे। वहीं दिव्यांगों के लिए भी खेल आयोजित किया जाएगा। बोड़ोलैंड स्पोर्ट्स मीट- 2024 का उद्घाटन बीटीआर के मुख्य कार्यकारी पार्षद (सीईएम) प्रमोद बोडो ने किया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रमोद बोडो ने कहा कि बोड़ोलैंड क्षेत्र खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। बोड़ोलैंड में ऐसे खिलाड़ी हैं जो सभी स्पर्धाओं में हिस्सा ले सकते हैं। बोड़ोलैंड में छह मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। कोकराझाड़ स्टेडियम का जल्द ही भूमि पूजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण

जोरहाट (हिंस)। जोरहाट जिला के टियक स्थित वीर लाचित बोरफुकन की विशाल प्रतिमा के काम की प्रगति का आज मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने जायजा लिया। मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने मेलांग मेटेली स्थित प्रधान मंत्री की उपस्थिति में आयोजित होने वाली रैली स्थल का दौरा किया। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने पार्टी के विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आयोजित होने वाली रैली को लेकर जागरूकता बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर और चराइदेव जिलों के 2 हजार 800 बूथों से लोगों को बैठक में किस तरह से लाया जाएगा उसको लेकर चर्चा की। उन्होंने सरकार के सहयोगी दल अगप के अध्यक्ष की मौजूदगी में अगप पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने की अपील

की। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री उक्त स्थान से वर्चुअली शिवसागर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे साथ ही 5 लाख 55 हजार 555 प्रधानमंत्री आवासों का भी उद्घाटन करेंगे।

भालुका रोड स्टेशन पर राधिकापुर-हावड़ा कुलिक एक्सप्रेस का नया ठहराव

गुवाहाटी (हिंस)। पूर्वोत्तर सीमा रेल (पूसीरे) ने रेल यात्रियों की सुविधा में एक कदम बढ़ाते हुए कटिहार मंडल अंतर्गत भालुका रोड स्टेशन पर ट्रेन संख्या 13053/13054 (हावड़ा-राधिकापुर-हावड़ा) कुलिक एक्सप्रेस का दो मिनट के लिए अतिरिक्त ठहराव कर दिया है। मालदा उत्तर के सांसद खगेन मुर्मु ने गुरुवार को भालुका रोड स्टेशन पर नए ठहराव के लिए कुलिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर मंडल के वरिष्ठ रेल अधिकारी और अन्य प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। पूसीरे के सीपीआरओ सब्यसाची डे ने बताया है कि हावड़ा से ट्रेन संख्या 13053 (हावड़ा- राधिकापुर) कुलिक एक्सप्रेस रवाना होने के बाद भालुका रोड 16.25 बजे पहुंचेगी और 16.27 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार राधिकापुर से ट्रेन संख्या 13054 (राधिकापुर- हावड़ा) कुलिक एक्सप्रेस रवाना होने के बाद भालुका रोड 07.29 बजे पहुंचेगी और 07.31 बजे प्रस्थान करेगी। इस नए ठहराव से स्थानीय लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो गई है।

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए खोला *वॉर रूम*

गुवाहाटी (हिंस)। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए असम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन की तीसरी मंजिल पर एक *वॉर रूम* खोला है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता मेहदी आलम बोरा ने आज बताया कि *वार रूम* नाम के इस नियंत्रण कक्ष की स्थापना राजीव भवन के तीन कमरों में की गई है, ताकि 12 कंप्यूटरों सहित सैकड़ों मोबाइल फोन के साथ चुनावी जंग में शामिल होने के लिए जमीनी स्तर पर संगठनात्मक लिंक स्थापित किया जा सके।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने किया विरोध प्रदर्शन

कामरूप (हिंस)। कामरूप (ग्रामीण) जिला के हाजो में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए असहयोग आंदोलन किया। हाजो एकीकृत बाल विकास परियोजना के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं की दुर्दशा को न समझने का सरकार पर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियमित कर्मचारी के रूप में मान्यता देने की इस दौरान मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा मजदूरी में बदलाव करने का वादा किया गया था, ऐसे में जब तक वादा पूरा नहीं होता है तब तक कार्यकर्ताओं और सहायकाओं को 12 हजार रुपए का भुगतान किया जाए। साथ ही सेवानिवृत्त कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं और मिनी कर्मियों को एकमुश्त सहायता राशि आगामी 20 अक्तूबर तक जारी करने की मांग की गई।

मणिपुर में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद

इंफाल (हिंस)। मणिपुर में हथियार और गोला बारूद की बरामदगी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद संयुक्त सुरक्षा बलों के अभियान में बरामद किया गया। मणिपुर पुलिस ने आज बताया कि सुरक्षा बलों द्वारा पहाड़ी और घाटी जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान और क्षेत्र प्रभुत्व चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान कांगपोकपी जिले से एक इंप्रोवाइज्ड प्रोजेक्टाइल लॉन्चर, एक इंप्रोवाइज्ड ग्रेनेड लॉन्चर और दो इंप्रोवाइज्ड प्रोजेक्टाइल बरामद किए गए। जबकि, मैगजीन के साथ एक 9 मिमी उजी सब मशीन गन, 9 मिमी के आठ लाइव राउंड, मैगजीन के साथ एक .32 पिस्तौल, दो हैंड ग्रेनेड, दो 80 डब्ल्यूपी स्मोक ग्रेनेड और दो 27 डेटोनेटर कांगपोकपी जिले से बरामद किया गया। इनके अलावा मैगजीन के साथ एक पीटी 303 राइफल, दो 12 इंच सिंगल बोर बैरल गन, 1 एक इम्प्रोवाइज्ड प्रोजेक्टाइल लॉन्चर, एक इम्प्रोवाइज्ड मोर्टार, छह नंबर 36 एचई हैंड ग्रेनेड, दो 2 इंच मोर्टार इल राउंड, दो इम्प्रोवाइज्ड मोर्टार राउंड, एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस वजन 3 किलोग्राम, चार 9 मिमी बॉल

लाइव राउंड, 1 एक 5.56 मिमी इंसास लाइव राउंड, एक 7.62 मिमी सीटीएन, 62 (बासठ) 7.62 मिमी फायर्ड केस, 45 (पैंतालीस) 5.56 मिमी फायर्ड केस तथा एक 2 इंच मोर्टार कैरीइंग केस कांगपोकपी जिले से बरामद किया गया। साथ ही दो संशोधित 6 इंच मोटर ट्यूब (देश में निर्मित पोम्पी), 11 जीवित पोम्पी राउंड, 10 फायर किए गए पोम्पी केस, एक 7.62 मिमी एसएलआर एक मैगजीन के साथ, चार 7.62 लाइव आरडी, 11 फायर 7.62 खाली केस, एक 9 मिमी पिस्तौल एक खाली मैगजीन के साथ, दो 12 बोर सिंगल बैरल बंदूक, डेटोनेटर के बिना दो नंबर 36 एचई हैंड ग्रेनेड, एक चीनी हैंड ग्रेनेड, एक डब्ल्यूपी स्मोक ग्रेनेड, दो बाइकार्ट स्ट्रिप (15 सेमी प्रत्येक) तथा एक चार्जर के साथ छह डब्ल्यूटी सेट डंपी रेंज बिष्णुपुर की तलहटी से बरामद किया गया।

बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया गुवाहाटी ने हाल की उपलब्धियों का मनाया जश्न

गुवाहाटी (विभास)। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया गुवाहाटी चैप्टर के अध्यक्ष बिजय सराफ के कुशल नेतृत्व में, उद्योग के विकास और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई हालिया उपलब्धियों और आगामी कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन ने डेटा सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए होटल *द लिली* में एक बेहद सफल सेमिनार का आयोजन किया। डेटा सुरक्षा पर प्रतिष्ठित वक्ता, कोलकाता से सीए भरत सरावगी ने निर्माण उद्योग के भीतर ज्ञान के आदान-प्रदान और नवाचार को बढ़ावा देते हुए अंतर्दृष्टि साझा की। उन्होंने उन विभिन्न तरीकों के बारे में भी अपडेट किया जिनके द्वारा हम अपने दैनिक व्यवसाय में अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने विभिन्न सॉफ्टवेयरों के बारे में अपडेट किया जिनका उपयोग हमारे आधिकारिक डेटा की सुरक्षा में किया जा सकता है। पैरामाउंट बिल्डर्स के सुरेश अग्रवाल ने डेटा सुरक्षा पर सेमिनार आयोजित करने के लिए वक्ता को धन्यवाद दिया। सामान्य बैठक के निर्णय की जानकारी सचिव शैलेश बाहेती ने दी। आगामी सत्र के लिए अध्यक्ष बिजय सराफ को सर्वसम्मति से पुन: नामित किया गया और दूसरे कार्यकाल के लिए सेवा जारी रखने के लिए चुना गया।

आचार्य श्री प्रमुख सागर महाराज ससंघ का विजयनगर में मंगल प्रवेश

गुवाहाट। आचार्य श्री प्रमुख सागर महाराज ससंघ ने बुधवार को विजयनगर के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मंगल प्रवेश किया। आचार्य श्री ससंघ ने गुवाहाटी चतुर्मास के पश्चात दिसपुर, पांडु, धारापुर, पलाशबाड़ी आदि जगहों से पद विहार कर बुधवार को विजयनगर पहुंचे जहां जैन समाज के श्रद्धालुओं ने अगवानी की। प्रचार प्रसार विभाग के मुख्य संयोजक ओम प्रकाश सेठी एवं सह संयोजक सुनील कुमार सेठी ने बताया कि मंगल प्रवेश पर ससंघ ने मुलनायक पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए। इस दौरान आचार्य श्री प्रमुख सागर महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। इस अवसर पर विजयनगर जैन समाज के

पदाधिकारीयों के अलावा काफी संख्या में समाज के सदस्य व स्थानीय लोग उपस्थित। मालूम हो कि आचार्य श्री ससंघ के पावन एवं धरियावद से आमंत्रित प्रतिष्ठित प्रतिष्ठाचार्य, हंसमुख शास्त्री के सान्निध्य एवं मार्गदर्शक में आगामी 24 एवं 25 फरवरी को सूर्योदय अहिंसा दिगम्बर जैन तीर्थ, सूर्यपहाड़ पर पुण्य प्राप्ति का अभूतपूर्व माध्यम वेदी प्रतिष्ठा का आध्यात्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी के अध्यक्ष महावीर जैन (गंगवाल)ने वेदी स्थापन की स्वीकृति प्रदान करने वाले सभी पुण्यार्जक समाजों, धर्मनिष्ठ परिवारों, वेदी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाली सभी महिलाओं, संगठनों, महानुभावों एवं वेदी में प्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान करने वाले सभी सौभाग्यशाली परिवारों से विनम्रता पूर्वक उपस्थित रहने का निवेदन किया है। प्रचार प्रसार के मुख्य संयोजक ओम प्रकाश सेठी ने सकल समाज बंधुओं से आग्रह किया हैं कि इस अनुष्ठान में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी बनकर अपने जीवन का कल्याण करे।

कलियाबोर सिविल अस्पताल में सीटी स्कैन और डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू

स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने किया उद्घाटन

नगांव (हिंस)। जिले के कलियाबोर के सब-डिविजनल सिविल अस्पताल में सीटी स्कैन और डायग्नोस्टिक सेंटर का गुरुवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने उद्घाटन किया। मंत्री ने यहां स्वर्गरथ सेवा का भी लोकार्पण किया। दरअसल, 14 सितंबर, 2022 को असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कलियाबोर सब-डिविजनल अस्पताल के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा की थी। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री ने रोगियों के लिए सीटी स्कैन और डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री महंत ने कहा कि कलियाबोर डिविजनल सिविल अस्पताल कलियाबोर के साथ ही पड़ोसी क्षेत्रों के रोगियों के लिए भी लंबे समय से चली लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि उलुवानी के श्रीमंत शंकरदेव ग्रामीण अस्पताल में पोस्टमार्टम केंद्र निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके बन जाने से क्षेत्र के पोस्टमार्टम केंद्र की कमी को दूर किया जा सकेगा। मंत्री केशव महंत ने कलियाबोर विधानसभा क्षेत्र के विधायक की विकास निधि से शव को ले जाने के लिए एक स्वर्गरथ को भी आम लोगों की सेवा में समर्पित किया।

रंगिया : 75वां महाविष्णु यज्ञ महोत्सव का आयोजन

रंगिया (विभास)। रंगिया के बिस्सेनाला में श्रीश्री महाविष्णु यज्ञ महोत्सव का 75वां आयोजन यानी इसकी हीरक जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर आयोजन समिति द्वारा 7 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं इसके पहले दिन के कार्यक्रम के तहत आज धार्मिक जुलूस का आयोजन किया गया। इस धार्मिक जुलूस में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार राजदीप बाइलुंग बरुवा उपस्थित रहे। धार्मिक जुलूस का उद्घाटन अखिल असम छात्र संस्था के अध्यक्ष उप्पल शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी 21 फरवरी को सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में असम के सुप्रशिद्ध गायक जुबिन गर्ग गीतों की प्रस्तुति देंगे।

विश्वनाथ ठाकुरबाड़ी नवनिर्मित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 18 फरवरी से

विश्वनाथ (विभास)। विश्वनाथ चारिआली नगर में अवस्थित लगभग 200 वर्ष पुराने ठाकुरबाड़ी मंदिर नूतन आलोक साज- सज्जा में प्रकाशमान हो उठा है। शहर के बीचों बीच सड़कों में रंगारंग रंगोली बनाने के साथ जयश्रीराम का ध्वजा, बैनर और रंगारंग लाइट आकर्षण का केंद्र बिंदु बना है। कल संध्या आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उक्त नवनिर्मित मंदिर में श्री राम दरबार, शिव-परिवार, राधा कृष्ण, हनुमान जी एवं माता रानी दरबार में अधिष्ठित ईश्वरीय मूर्तियों के लिए सांकेतिक प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुभारंभ माघ शुक्ल, नवमी, विक्रम संवत, रविवार, दिनांक 18 फरवरी, 2024 को होगा तथा माघी पूर्णिमा, विक्रम संवत 2080, शनिवार, दिनांक 24 फरवरी, 2024 को पूर्णाहुति के रूप में संपन्न होगा। इस अवसर पर विश्वनाथ चारिआलि नगर का वातावरण भक्तिमय होने जा रहा है। सांकेतिक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम इस प्रकार है - 18 फरवरी को कलश शोभायात्रा, 19 फरवरी को वेदी पूजन, 20 फरवरी को अन्न, वस्त्र, पुष्प, फल आदि अधिवास कार्यक्रम, 21 फरवरी को प्रतिष्ठित भगवान को दिव्य स्नान, नगर परिक्रमा तथा शयन (श्य्याधिवास) कार्यक्रम, 22

फरवरी को प्रात: 5 बजे से 8 बजे अचल (स्थिर) प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं प्रात: 9 बजे से भव्य महाआरती, 23 फरवरी को वेदी पूजन तथा चतुर्थी कर्म समारोह तथा राम विवाह एवं शिव विवाह एवं 24 फरवरी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूर्णाहुति छत तथा महाप्रसाद वितरण। मंदिर समिति ने समारोह के सभी कार्यक्रमों में लोगों का उपस्थिति का आग्रह किया हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष शंकरलाल पारिक एवं सचिव प्रभुनाथ सिंह के अनुसार समारोह की तैयारी जोरो पर चल रही है। इस कार्यक्रम में असंख्य श्रद्धालुओं की भीड़ होने का उम्मीद जताई जा रही है।

संपादकीया

पाकिस्तान जनादेश के मायने

पाकिस्तान और जम्हूरियत परस्पर-विरोधी यथार्थ हैं। पाकिस्तान में चुनाव दिखावटी होते हैं और हुकूमत 'फौज की कठपुतली' होती है। यदि लोकतंत्र होता, तो हुकूमत और सियासत में सेना की निर्णायक भूमिका क्यों होती? प्रधानमंत्री फौज के मोहताज क्यों होते? फौज चुनावों को भी प्रभावित कैसे कर सकती थी? लेकिन इस बार अवाम ने फौज को गच्चा दे दिया है। उसके फरमानों को खारिज कर दिया है और जम्हूरियत की ताकत की एक बानगी-सी पेश की है। नतीजतन जेल में कैद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बर्खास्त पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (पीटीआई) के समर्थक निर्दलियों ने 101 सीटें जीती हैं, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन और भुट्टो-जरदारी की पीपीपी क्रमशः 75 और 54 सीटों तक ही ठिठक गई हैं। दोनों बहुमत के आंकड़े 134 से बहुत दूर हैं। खुद पीपीपी मुखिया बिलावल भुट्टो चुनाव हार गए हैं। अवाम ने इमरान खान के एआई अवतार और आह्वानों को सुना और स्थानीय स्तर पर जनादेश की बुनियाद तैयार की। फौज की लाठी, बंदूक और घुड़कियां नाकाम रहीं। कदाचित यह किसी भी देश का पहला जनादेश है कि निर्दलीय सबसे अधिक सीटों पर जीते हैं। पाकिस्तान में चुनाव खूब छापे गए, फर्जी वोट डाले गए और फिर नतीजों में धांधलियां की गईं। यदि ऐसा नहीं होता, तो निर्दलीय अपने दम पर ही बहुमत हासिल कर सकते थे! वहां की कंगारू अदालतों में चुनाव धांधलियों के असंख्य मामले दर्ज हैं। क्या पाकिस्तान में अवाम को चुनावी इंसाफ मिलेगा? हालांकि परंपरागत सियासी पार्टियों को बहुमत हासिल नहीं हुआ है, फिर भी गठबंधन के लिए सौदेबाजी की जा रही है। यह खबर पाकिस्तान के मीडिया के जरिए ही सामने आई है कि पीपीपी के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने पीएमएल-एन के नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने शर्त रखी है कि बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाया जाए। बदले में उनकी पार्टी नवाज शरीफ की बेटी मरियम को पंजाब की मुख्यमंत्री बनाने को समर्थन दे सकती है। जरदारी के इस मास्टर स्ट्रोक से शरीफ खानदान दुविधा में है, क्योंकि जरदारी की बात मानने के मायने होंगे कि शरीफ कुनबे की सियासत समाप्त हो सकती है। शरीफ कुनबे के लिए पंजाब बहुत मायने रखता है, क्योंकि देश की आबादी से लेकर अर्थव्यवस्था तक पंजाब की हिस्सेदारी 60 फीसदी से ज्यादा है। पाक मीडिया का विश्लेषण है कि जरदारी राष्ट्रपति पद की पेशकश पर सहमत हो सकते हैं। उधर इमरान खान ने एआई तकनीक से निर्दलीय विजेताओं का आह्वान किया है कि वे किसी से गठबंधन न करें। अवाम ने हमें भ्रष्ट सियासतदानों के खिलाफ जनादेश दिया है, तो ऐसे लोगों के साथ हुकूमत कैसे बनाई जा सकती है? यह विकल्प भी सामने आया है कि निर्दलीय अपना गुट बनाकर एक नई पार्टी के गठन पर भी विचार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उसे मान्यता देगा अथवा नहीं, फिलहाल यह अनिश्चित है। पीटीआई समर्थक निर्दलीय, अंततः, भुट्टो परिवार की पार्टी पीपीपी में भी विलय करने की सोच रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान में आम चुनाव होने के बाद भी अराजकता का माहौल है। इमरान खान के आह्वानों ने अवाम, खासकर नौजवानों, को उत्तेजित और आक्रोशित किया है। ऐसे में एक जिम्मेदार हुकूमत बनना लाजिमी है।

जेल में कैद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बर्खास्त पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (पीटीआई) के समर्थक निर्दलियों ने 101 सीटें जीती हैं, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन और भुट्टो-जरदारी की पीपीपी क्रमशः 75 और 54 सीटों तक ही ठिठक गई हैं। दोनों बहुमत के आंकड़े 134 से बहुत दूर हैं। खुद पीपीपी मुखिया बिलावल भुट्टो चुनाव हार गए हैं। अवाम ने इमरान खान के एआई अवतार और आह्वानों को सुना और स्थानीय स्तर पर जनादेश की बुनियाद तैयार की। फौज की लाठी, बंदूक और घुड़कियां नाकाम रहीं। कदाचित यह किसी भी देश का पहला जनादेश है कि निर्दलीय सबसे अधिक सीटों पर जीते हैं। पाकिस्तान में चुनाव खूब छापे गए, फर्जी वोट डाले गए और फिर नतीजों में धांधलियां की गईं। यदि ऐसा नहीं होता, तो निर्दलीय अपने दम पर ही बहुमत हासिल कर सकते थे! वहां की कंगारू अदालतों में चुनाव धांधलियों के असंख्य मामले दर्ज हैं। क्या पाकिस्तान में अवाम को चुनावी इंसाफ मिलेगा? हालांकि परंपरागत सियासी पार्टियों को बहुमत हासिल नहीं हुआ है, फिर भी गठबंधन के लिए सौदेबाजी की जा रही है। यह खबर पाकिस्तान के मीडिया के जरिए ही सामने आई है कि पीपीपी के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने पीएमएल-एन के नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने शर्त रखी है कि बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाया जाए। बदले में उनकी पार्टी नवाज शरीफ की बेटी मरियम को पंजाब की मुख्यमंत्री बनाने को समर्थन दे सकती है। जरदारी के इस मास्टर स्ट्रोक से शरीफ खानदान दुविधा में है, क्योंकि जरदारी की बात मानने के मायने होंगे कि शरीफ कुनबे की सियासत समाप्त हो सकती है। शरीफ कुनबे के लिए पंजाब बहुत मायने रखता है, क्योंकि देश की आबादी से लेकर अर्थव्यवस्था तक पंजाब की हिस्सेदारी 60 फीसदी से ज्यादा है।

2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम का प्रावधान है

ईपीएफ में न्यूनतम पेंशन का सवाल

डा. अश्विनी महाजन

भारत सरकार द्वारा 1995 में किया गया था, जिसे 2014 में 1000 रुपए प्रतिमाह तक बढ़ा दिया गया, लेकिन कर्मचारी पिछले कुछ समय से मूल पेंशन में वृद्धि करने और अन्य मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। सभी के लिए ज्यादा पेंशन : ईपीएस स्कीम के तहत अभी सभी कर्मचारियों के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन का प्रावधान है। लेकिन मजदूर संगठनों द्वारा बार-बार यह मांग की जा रही है कि सभी सदस्यों को ज्यादा पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। अलग-अलग संगठनों ने इसके लिए अलग-अलग पेंशन राशि की मांग की है।

एंप्लाइज पेंशन स्कीम (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत, ऐसे कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य हैं, उनके लिए न्यूनतम पेंशन का प्रावधान पहली बार भारत सरकार द्वारा 1995 में किया गया था, जिसे 2014 में 1000 रुपए प्रतिमाह तक बढ़ा दिया गया, लेकिन कर्मचारी पिछले कुछ समय से मूल पेंशन में वृद्धि करने और अन्य मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। सभी के लिए ज्यादा पेंशन : ईपीएस स्कीम के तहत अभी सभी कर्मचारियों के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन का प्रावधान है। लेकिन मजदूर संगठनों द्वारा बार-बार यह मांग की जा रही है कि सभी सदस्यों को ज्यादा पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। अलग-अलग संगठनों ने इसके लिए अलग-अलग पेंशन राशि की मांग की है। इस संबंध में, देश के सबसे बड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और पेंशन अंतिम आहरित वेतन का आधा तय किया जाना चाहिए, और ईपीएस कोई अपवाद नहीं होना चाहिए।

अलग-अलग प्रकार की पेंशन : गौरतलब है कि देश में कर्मचारियों के लिए उनके नियोक्ता के हिसाब से अलग-अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का प्रावधान है। एक तरफ 2004 से पूर्व में नियुक्त सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें सरकार उनकी पूरी सेवा अवधि के बाद आखिरी वेतन के आधे के बराबर मासिक पेंशन के रूप में प्रदान करती है। 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम का प्रावधान है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा भविष्य निधि में योगदान दिया जाता है, जिसे नई पेंशन स्कीम के नियमों के अनुसार प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, और उसी संचित निधि में से योगदान पर आधारित पेंशन देने का प्रावधान है। नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी भी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की मांग कर रहे हैं और कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली भी कर दी है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी ईपीएफओ के अंतर्गत आते हैं। ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा राशि ईपीएफओ में जमा की जाती है और इस प्रकार से हर कर्मचारी द्वारा जमा कुल राशि पर हर साल घोषित ब्याज दर के हिसाब से ब्याज लगाया जाता है। अपने सेवा काल के दौरान जमा की गई राशि और

साथ ही ब्याज पर भुगतान सेवानिवृत्ति अथवा नौकरी छोडने या छूटने पर कर्मचारी को कर दिया जाता है। वर्ष 1995 से ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को उनकी जमा राशि और ब्याज के अलावा न्यूनतम पेंशन का प्रावधान किया गया और उसे बाद में 1000 रुपए प्रतिमाह तक बढ़ाया गया। इसके बाद कर्मचारियों की लगातार यह मांग रही है कि यह राशि अत्यंत कम है और इसमें वृद्धि होनी चाहिए। यही नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गैर ईपीएफओ कर्मचारियों और मजदूरों एवं स्वरोजगार युक्त छोटे व्यापारियों के लिए नई शुरुआत की गई है।

गैर ईपीएफओ कर्मचारियों और मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना प्रारंभ की गई है एवं व्यापारी और स्वरोजगार युक्त व्यक्तियों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। इन दोनों योजनाओं में 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह तक मासिक योगदान करना होगा। एक बार जब लाभार्थी 18-40 वर्ष की प्रवेश आयु में योजना में शामिल हो जाता है, तो लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना होता है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ग्राहक को, जैसा भी मामला हो, पारिवारिक पेंशन के लाभ के साथ 3000 रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन डीबीटी द्वारा प्राप्त होगी। यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी ग्राहक ने लगातार योगदान का भुगतान नहीं किया है, तो उसे सरकार द्वारा तय किए गए दंड शुल्क, यदि कोई हो, के साथ-साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके अपने योगदान को नियमित करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकारी बैंकों और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में सामाजिक सुरक्षा की अलग-अलग व्यवस्था है। यानी कहा जा सकता है कि देश हर कम या ज्यादा सभी आय वर्गों के कर्मचारी और स्वरोजगार युक्त व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न प्रकार की रचना देश में बनी हुई है। गौरतलब है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और स्वरोजगार युक्त लोगों को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान मोटे तौर पर तब करना होगा जब वर्तमान में इसके लिए जिन 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों ने सदस्यता ली है। यानी इस योजना के लिए राशि का प्रावधान कम से कम 20 वर्ष से पहले नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि ईपीएफओ के सदस्यों को यदि ऊंची पेंशन देनी पड़े तो उसकी देनदारी तुरंत ही ईपीएफओ के संचित फंड पर पड़ेगी और इतनी पेंशन देने के बाद ईपीएफओ की संचित राशि धीरे-धीरे समाप्त हो सकती है। ऐसे में ईपीएफओ में अपना योगदान देने वाले कर्मचारियों को भविष्य में उनकी राशि वापस करने में कठिनाई हो सकती है। केंद्र सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ईपीएसए 1995 के तहत पेंशन फंड एक एकत्रित फंड है। पेंशन निधि में, व्यक्तिगत खाते नहीं रखे जाते हैं। ईपीएसए 1995 के सदस्य सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर उनकी पात्रता के आधार पर निकासी लाभ या पेंशन के लिए पात्र हैं। 31.03.2019 तक फंड के एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार, पेंशन फंड घाटे में है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में नियोक्ता के योगदान के रूप में वेतन के 1.16 प्रतिशत के रूप में लगभग 8000 करोड़ रुपए का योगदान दिया जा रहा है। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन के 1000 रुपए के भुगतान के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का योगदान दिया जा रहा है। इसलिए, न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाए जाने के बाद बजट से बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होगी, और पूरा बोझ केंद्र सरकार पर पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार ईपीएफओ में इस पेंशन को बढ़ाने का फैसला लेती है तो उसे उसी अनुपात में इसका बोझ उठाना होगा, इसलिए सरकार को यह फैसला लेने से पहले अपने बजटीय संसाधनों को ध्यान में रखना होगा।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय : सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 के अपने निर्णय में 15 हजार से ऊपर के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत यह निर्देश दिया कि ऐसे कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं का योगदान 8.33 प्रतिशत की बजाय 9.49 प्रतिशत रहेगा। इस अतिरिक्त राशि का भुगतान केंद्र सरकार करती है।

दृष्टि कोण

MSP गारंटी कानून की माँग आखिर कैसे किसान और देश के हित में नहीं है?

फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाने की मांग को लेकर किसान एक बार फिर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली की ओर बढ़ने के सफर में यह आंदोलनकारी जिस तरह अवरोधकों को तोड़ रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं उससे साफ प्रदर्शित हो रहा है कि ये आंदोलनकारी लोग किसान हैं ही नहीं। क्योंकि किसान कभी उपद्रव नहीं मचाता, किसान कभी पुलिस पर पत्थर नहीं मारता, किसान कभी बंदूक नहीं लहराता, किसान कभी लाठियां नहीं भांजता। जिस तरह से ये आंदोलनकारी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं वह यह भी प्रदर्शित कर रहा है कि ऐन लोकसभा चुनावों के पहले यह आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार सत्ता में पहुँचने से रोकने के लिए ही खड़ा किया जा रहा है। हम आपको याद दिला दें कि हाल ही में भारत ने आरोप लगाया था कि कनाडा हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए प्रश्न उठता है कि कहीं कनाडा में सरकारी प्रोत्साहन पा रहे खालिस्तानी तत्वों द्वारा तो इस आंदोलन को हवा नहीं दी जा रही है? हम आपको बता दें कि किसानों का पिछला आंदोलन जहां मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए था वहीं यह नया आंदोलन मोदी

सरकार से एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए खड़ा किया जा रहा है। यहां सवाल उठता है कि यदि सरकार से कानून बनवाना था तो संसद सत्र के चलते समय क्यों नहीं सरकार से बात की गयी? अब जब 17वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका है तो सरकार कहां से कानून बना देगी? यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या एमएसपी कानून बना देने से ही किसानों की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? अभी सरकार लगभग 22 फसलों का एमएसपी देती है। सवाल उठता है कि क्या यह सभी 22 फसलें किसान एमएसपी पर ही बेचते हैं? कई बार ऐसा होता होगा कि कई फसलें एमएसपी से भी कम या एमएसपी से ज्यादा दर पर बेची जाती होंगी। दरअसल फसलों के दाम बहुत हद तक हालात पर निर्भर करते हैं इसलिए एमएसपी घोषित होने के बावजूद उससे कम या ज्यादा दाम पर फसलें बेची जाती रही हैं। एमएसपी की मांग पर अड़े किसानों को यह भी देखना चाहिए कि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में उनके लिए क्या किया है। कोरोना महामारी आई, कई देशों के युद्ध और संघर्ष के चलते वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई लेकिन देश में यूरिया के दाम नियंत्रण में रहे और किसानों की जेब पर बोझ नहीं पड़ने दिया गया। मोदी सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने का अतिरिक्त प्रबंध भी किया। किसानों को समझना होगा कि एमएसपी से उनका वास्तविक भला नहीं होगा। उनका भला तब होगा जब उनकी कृषि लागत कम होगी और उनकी उपज बिना किसी बिचौलिये के मंडियों तक पहुँचेगी। किसानों का वास्तविक भला तब होगा जब वह स्टार्टअप के इस युग में अपने कृषि उत्पादों की मार्केटिंग करने का प्रयास करेंगे। किसानों को इस सबमें मदद के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ना कि सभी फसलों के लिए एमएसपी गारंटी कानून जैसी अव्यवहारिक मांग करनी चाहिए। बहरहाल, किसानों को यह बात भी समझनी होगी कि सरकार यदि एमएसपी गारंटी कानून लाई तो हर साल उस पर 10 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह बोझ कितना बड़ा है इसे आसान शब्दों में समझाएं तो आपको बता दें कि यह लगभग उस व्यय (11.11 लाख करोड़ रुपये) के बराबर है जो सरकार ने हाल के अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे के लिए अलग से रखा है। सवाल यह भी है कि यह 10 लाख करोड़ रुपया कहां से आएगा? क्या सरकार बुनियादी ढांचे पर हो रहे खर्च में कटौती करे या रक्षा खर्च में कटौती करे या चिकित्सा अथवा शिक्षा क्षेत्र में हो रहे खर्च में कटौती करे या जनता पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नये टैक्स लगाये? इसमें कोई दो राय नहीं कि वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, हर क्षेत्र पर महामारी का विपरीत असर पड़ा लेकिन अन्नदाता की बदौलत भारत बहुत जल्दी इस हालात से उबरने में सक्षम रहा। लेकिन अन्नदाता की जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है, उसे यह सुनिश्चित करने के लिए देश के साथ खड़े रहना चाहिए कि देश का खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ाने या देश को वित्तीय आपदा में धकेलने के प्रयासों को विफल किया जाये। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाये रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी है।

कुछ अलग

हिमाचल का ऑडिट जरूरी

ऑडिट की दिशा में हिमाचल सरकार मंत्रिमंडल की तीन उपसमितियों के तहत अपने कदमों को नई जगह बना रही है। अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग की उपयोगिता में भर्ती परीक्षाओं की सलामती का हिसाब मुकर्रर होगा, तो लीज या विभागों को आबंटित अनुपयोगी जमीन की समीक्षा भी होगी। एक अन्य उपसमिति विभागों की अनुपयोगी या रिक्त पड़ी संपत्तियों का मूल्यांकन करेगी। प्रदेश पहली बार अपनी जमीन की उपलब्धता तथा संपत्तियों की उपयोगिता का मूल्यांकन कर रहा है। जाहिर है ऐसे कदमों से सत्ता की पारदर्शिता में प्रणाली की जवाबदेही बढ़ेगी। सार्वजनिक जमीनों के विभागीय इस्तेमाल का आबंटन कई स्थानों पर बिना किसी इस्तेमाल के मुंह चिढ़ा रहा है, तो कई अन्य स्थानों पर सरकारी संपत्तियां ही अनुपयोगी साबित हो रही हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तरक्की के पैमाने ऐसी ही पैमाइश करते रहे। यही नहीं सरकारी इमारतों के नक्शों में न तो भविष्य की कल्पना रही और न ही उपलब्ध स्थान के बेहतर इस्तेमाल की परिकल्पना। सरकारी भवनों की आयु में निरंतर गिरावट की वजह इनके निर्माण में बरती गई ढील और सामग्री की गुणवत्ता में आई कमी है। हर नया बजट, हर नई परियोजना और हर नई सरकार का मुलम्मा यूं ही चढ़ता गया और इमारतों के ऊपर इमारतें चढ़ती गईं। कार्यालयों के स्तरोन्नत होते ही नए भवनों को मिला बजट फिजूलखर्ची पर उतर आता है, नतीजतन इसकी उपयोगिता की छत सिकुड़ जाती है। जाहिर है सरकार इस बहाने सार्वजनिक भूमि तथा संपत्तियों के उपयोग और उपयोगिता को सुदृढ़ करना चाहती है। दरअसल हिमाचल में सार्वजनिक भूमि का आबंटन विभागीय तौर पर होता है और इसके कारण महकमे इसका सदुपयोग नहीं करते। विभागीय कार्यालयों के साथ आवासीय व्यवस्था के चक्कर में भी इसकी उपयोगिता व स्कोप घट जाता है। प्रशासनिक शहरों में सार्वजनिक भूमि का गलत इस्तेमाल या फिजूलखर्ची का आलम यह है कि कुछ विभागों की आवासीय कोठियां ही अधिकतर भूमि को घेर कर इसे बेकार कर रही हैं। धूमल सरकार ने संयुक्त कार्यालय भवन निर्माण को प्राथमिकता देते हुए एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ विभाग आज भी अपने बजट और प्रोजेक्ट के तहत इमारतों पर कलई चढ़ा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में सरकारी संपत्तियों के विस्तार, इस्तेमाल, आबंटन व भविष्य की योजनाओं के लिए एक सार्वजनिक एस्टेट प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके तहत निजी विभाग के बजाय इस अथारिटी के तहत संपत्तियों का संचालन करके अधिकतम उपयोग बढ़ाया ता सकता। केवल स्कूल, स्वास्थ्य व पुलिस संस्थानों को एक सीमा के भीतर अलग से मालिकाना हक मिलें, जबकि हर विभाग के दफ्तर को सार्वजनिक एस्टेट प्रबंधन प्राधिकरण के तहत छत उपलब्ध करानी होगी। इतना ही शहरों में स्थित कुछ विभागों को कार्यालयों की उपयोगिता ग्रामीण परिवेश में बढ़ानी चाहिए। मसलन जिला मत्स्य अधिकारी का कार्यालय नदी या बांध के समीप, कृषि व बागबानी अधिकारी के कार्यालय ग्रामीण इलाकों में, उद्योग विभाग को औद्योगिक केंद्रों तथा वन विभाग के दफ्तरों को जंगलों में भेज देना चाहिए। इतना ही नहीं, शहरी योजना या यातायात व्यवस्था में अड़चनें पैदा कर रहीं सरकारी इमारतों को भी चरणबद्ध तरीके से हटाने की दिशा में प्रयास करने चाहिएं। बहरहाल सुक्खू सरकार ने उप समितियों के जरिए एक अच्छी शुरुआत की है और भविष्य इसी तर्ज पर राज्य के अलग-अलग सर्वेक्षण आवश्यक हैं। राज्य में पार्किंग व्यवस्था, कूड़ा कर्कट प्रबंधन, अनावश्यक कार्यालयों तथा सार्वजनिक उपक्रमों की खामियों का भी स्पष्ट मूल्यांकन करना चाहिए। इसी तरह एक उपसमिति के तहत बड़े शहरों, कस्बों व महत्त्वपूर्ण स्थलों के भविष्य के लिए भूमि बैंक स्थापित करने के लिए एक जवाबदेह व्यवस्था बनानी पड़ेगी।

देश दुनीया से

लॉजिस्टिक लागत घटने का परिदृश्य

देश में जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट तथा यातायात के साधनों में बड़े निवेश और आधुनिकीकरण जैसे अहम कारणों से लॉजिस्टिक लागत में बड़ी कमी आई है। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 के तहत भी भारत 6 पायदान की छलांग के साथ 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत 2018 में इस सूचकांक में 44वें तथा 2014 में 54वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जिस रणनीतिक रूप से पीएम गति शक्ति योजना 2021 और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) 2022 का कार्यान्वयन शुरू किया गया है, उससे भारत में लॉजिस्टिक लागत में कमी का परिदृश्य लगातार उभरकर दिखाई देने लगा है।

इन दिनों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत में लॉजिस्टिक लागत घटने से संबंधित जो अध्ययन रिपोर्टें प्रकाशित हो रही हैं, उनके आधार पर भारत में वर्ष 2024 में विनिर्माण, कारोबार, निर्यात और रोजगार के मौके बढ़ाने में घटती हुई लॉजिस्टिक लागत की अहम भूमिका होगी। हाल ही में उद्योग व आंतरिक व्यापार संवद्र्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने 'भारत में लॉजिस्टिक्स लागत : आकलन और दीर्घावधि फ्रेमवर्क' रिपोर्ट 2023 को जारी करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7.8 से 8.9 प्रतिशत के बीच रही है। इस लॉजिस्टिक लागत में यातायात लागत, वेयर हाउसिंग और भंडारण लागत, सहायक सहायता सेवाओं की लागत, पैकेजिंग की लागत, बीमा लागत और अन्य संचालन लागतें शामिल की गई हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकानॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा विश्व बैंक के निर्धारित मापदंडों पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट तथा यातायात के साधनों में बड़े निवेश और आधुनिकीकरण जैसे अहम कारणों से लॉजिस्टिक लागत में बड़ी कमी आई है। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 के तहत भी भारत 6 पायदान की छलांग के साथ 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत 2018 में इस सूचकांक में 44वें तथा 2014 में 54वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जिस रणनीतिक रूप से पीएम गति शक्ति योजना 2021 और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) 2022 का कार्यान्वयन शुरू किया गया है, उससे भारत में लॉजिस्टिक लागत में कमी का परिदृश्य लगातार उभरकर दिखाई देने लगा है। ज्ञातव्य है कि सामान्यतः वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल की लागत पहले क्रम पर और मजदूरी की लागत दूसरे क्रम पर होती है। फिर लॉजिस्टिक लागत का क्रम आता है। उत्पादों एवं वस्तुओं को उत्पादित स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचाने तक लगने वाले परिवहन, भंडारण व अन्य खर्च को लॉजिस्टिक खर्च कहा जाता है। जहां डीपीआईआईटी के द्वारा हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट में लॉजिस्टिक लागत नौ फीसदी से भी कम रहने की बात कही गई है, वहीं लॉजिस्टिक से जुड़े कई संगठनों की अध्ययन रिपोर्टों में भारत में लॉजिस्टिक की लागत जीडीपी के 10 फीसदी से अधिक होने के अनुमान भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वस्तुतः कोई एक वर्ष पहले 17 सितंबर 2022 को लांच हुई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी का लक्ष्य पांच साल में देश में लॉजिस्टिक लागत को घटाकर 8 फीसदी करना है। साथ ही इसका लक्ष्य 2030 तक कम लॉजिस्टिक खर्च वाले दुनिया के टॉप 25 देशों की सूची में देश को भी कम लॉजिस्टिक लागत वाले देश के रूप में स्थान दिला पाना भी है। इसका लक्ष्य माल परिवहन की लागत घटाकर सभी प्रकार के उद्योग-कारोबार को बढ़ावा देना और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना भी है। चूंकि वर्तमान में लॉजिस्टिक्स का ज्यादातर काम सडक़ों के जरिए होता है, अतएव अब इस नीति के तहत रेल ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जा रहा है। लगभग 50 प्रतिशत कार्गो को रेलवे के जरिए भेजे जाने का लक्ष्य आगे बढ़ाया जा रहा है और सडक़ों पर ट्रैफिक को कम किया जा रहा है। देश में बुनियादी ढांचे का तेजी से निर्माण होने लगा है। साथ ही लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ड्रोन का भी इस्तेमाल शुरू हुआ है। निःसंदेह नई लॉजिस्टिक नीति और करीब 100 लाख करोड़ रुपए की महत्त्वाकांक्षी पीएम गतिशक्ति योजना एक सिक्के के दो पहलू की तरह ही हैं। गति शक्ति योजना का मुख्य लक्ष्य देश में एकीकृत रूप से बुनियादी ढांचे का विकास करना है। वस्तुतः देश में सडक़, रेल, जलमार्ग आदि के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 16 मंत्रालयों और विभागों के बीच पीएम गतिशक्ति योजना के तहत सहकार व समन्वय बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। गतिशक्ति योजना के तहत पिछले दो वर्षों में विभिन्न विभागों की अवसंरचना विकास से जुड़ी गतिविधियों को एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल के तहत लाए जाने का काम हुआ है। साथ ही अब रेलवे, सडक़, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, सार्वजनिक परिवहन और लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में चिन्हित किए गए सात इंजनों के तहत भारतमाला (राजमार्ग), सागरमाला (तटीय नौवहन), उड़ान (वायु सेवाओं), भारत नेट (दूरसंचार सेवाओं), रेलवे विस्तार और अंतर्देशीय जलमार्ग विस्तार जैसी महत्त्वपूर्ण योजनाओं को समन्वित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।

आप का नजरीया

राजनीति में रंगे भारत रत्न

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पांच भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा देशभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसलिए कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के नेपथ्य में छिपी मंशा या एजेंडे को देश का अनपढ़ मतदाता भी बखूबी समझ रहा है। एक ऐसा पुरस्कार जो 1954 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक गरिमा, गौरव और प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है, का राजनीतिक मन्सूबों के लिए इस्तेमाल शायद पहले कभी बड़े स्तर पर नहीं हुआ। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवानी, चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामिनाथन को भारत रत्न से विभूषित किए जाने की आलोचना इसलिए हो रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इन्हें 'ट्रम्प कार्ड' के रूप में प्रयोग कर चुनावी समीकरण, गठबन्धन साधना चाहती है, ताकि तीसरी बार वह सत्तासीन हो सके। धारा 370 हटाने से लेकर राम मन्दिर के निर्माण आदि में जो कामयाबी, लोकप्रियता भाजपा ने हासिल की है, उससे देशभर में यह माहौल बनाया जा चुका है कि तीसरी दफा भाजपा की विजय निश्चित है। गोदी मीडिया तो अपने सर्वे में भाजपा को जिता ही चुका है। ऐसे में भारत रत्न को हथियार बनाकर लोकसभा में 400 का आंकड़ा पार करने की शायद जरूरत नहीं थी। लेकिन साम, दाम, दण्ड, भेद से चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है। कर्पूरी ठाकुर बिहार में हाशिए पर सिमटे लोगों यानी दलित पिछड़ों की आवाज थे। लेकिन यह पुरस्कार उन्हें ऐसे वक्त मिला है जब 'पलटू राम' सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा के पाले में पुनः लुढक़ने के लिए तैयार बैठे थे। कर्पूरी ठाकुर निश्चित रूप से इस पुरस्कार के हकदार हैं, पर यह उन्हें कई दशक पहले मिल जाना चाहिए था। लालकृष्ण आडवानी को हिन्दुत्व के एजेन्डे को बढ़ावा देने के लिए भारत रत्न मिला। राम मन्दिर की प्राण प्रतिष्ठा से चन्द रोज़ बाद। लेकिन जानकार भूले नहीं हैं कि रामरथ यात्रा मंडल कमीशन द्वारा ओबीसी तबके को आरक्षण देने के जवाब में आरम्भ हुई थी। देशभर में जिस-जिस शहर से आडवाणी की यात्रा गुजरी थे, दंगे हुए। बेकसूर लोग मौत के घाट उतारे गए। आडवाणी का देश को एक सूत्र में जोडऩे, भाईचारा, सद्भाव या धर्मनिरपेक्षता को सुदृढ़ करने में शून्य योगदान रहा है। संसद पर हमला उनके उप प्रधानमन्त्री व गृहमन्त्री रहते हुआ तो कारगिल में इंटेलीजेन्स फेलियर उनके कार्यकाल की देन है। चौधरी चरण सिंह ताउम्र नीतीश बाबू की तरह दल बदलते रहे। उनके पोते जयन्त चौधरी को एनडीए गठबंधन में शामिल करने, यूपी में किसानों, जाटों के वोटों को भाजपा की झोली में लाने के लिए एक भारत रत्न को कुर्बान किया गया। 6 दिसम्बर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढहायी जा रही थी तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। यूपी में मुलायम सिंह ने कारसेवकों पर हमले करवाए। उनकी लाशें अयोध्या की सरयू नदी में तैरती मिलीं। पीवी मूकदृष्टा बने रहे। देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बचाने या बनाए रखने में विफल रहे। वे किसी भी मायने में भारत रत्न जैसे सम्मान के पात्र नहीं थे। लेकिन सरकार ने कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए उन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया है या फिर बाबरी मस्जिद ध्वंस को चुपचाप सह लेने के लिए और आडवाणी, उमा भारती जैसे नेताओं का मूक साथ देने के लिये? एमएस स्वामिनाथन का योगदान जितना बड़ा है, उसके समक्ष भारत रत्न जैसा पुरस्कार छोटा है। लेकिन यह उन्हें जीते जी कांग्रेस सरकारों की ओर से मिलना चाहिए था।

किसान आंदोलन के मौजूदा हाल का प्रशासन जिम्मेदार : प्रो. रामगोपाल यादव

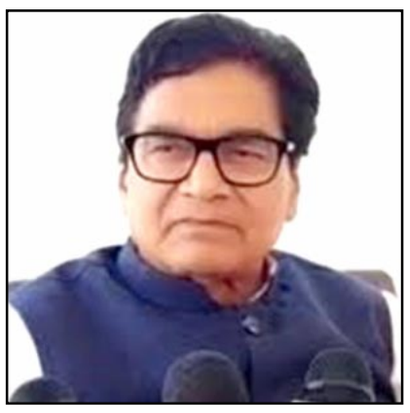

मैनपुरी (हिंस)। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे किसानों के आंदोलन का जो हाल है, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। किसानों के ऊपर बम, गोलियां बरसाए जा रहे हैं। बल प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यह बातें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने कही। वे गुरुवार को मैनपुरी पहुंचे थे। प्रोफेसर रामगोपाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि किसानों पर बर्बरता नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा का दिल्ली से पत्ता कट जाएगा। पार्टी के सहयोगी दल की विधायक पल्लवी पटेल द्वारा सपा के राज्यसभा उम्मीदवारों को वोट न देने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि न करें वोट, कोई ऐसा नहीं है जो राज्यसभा में वोट न करे। जो वोट नहीं करेगा, उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसलिए वोट तो सभी विधायकों को देना होगा।

पंजाब व दिल्ली की सरकारों ने भड़काया किसान आंदोलन : मुख्यमंत्री मनोहर लाल

दोबारा नहीं होने देंगे लाल किले जैसी घटना

चंडीगढ़ (हिंस)। किसान संगठनों के आंदोलन पर चुप्पी तोड़ते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इस आंदोलन के लिए सीधे तौर पर पंजाब व दिल्ली की सरकारें जिम्मेदार हैं। गुरुवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं है लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इन किसान संगठनों को दिल्ली व पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकारों का खुला समर्थन हासिल है। यदि ऐसा नहीं होता तो इन किसान संगठनों को पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार उन्हें दिल्ली कूच के लिए निकलने ही नहीं देती। मनोहर लाल ने कहा कि पिछले आंदोलन का अनुभव हमारे पास है। हम किसी सूरत में दिल्ली के लाल किले जैसा कांड नहीं होने दे सकते। किसान संगठनों को मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए। उन्हें कानून व्यवस्था को तोड़कर दिल्ली कूच की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने पंजाब की सीमा में बैरिकेडिंग नहीं की। जितनी भी बैरिकेडिंग है, वह हरियाणा की सीमा में है। पंजाब के किसान संगठन एमएसपी व कर्जमाफी की जो मांग कर रहे हैं, वह हालांकि हरियाणा सरकार से जुड़ी नहीं है। इन मांगों का सीधा संबंध केंद्र सरकार से है लेकिन पंजाब के किसान संगठनों को यह समझने की जरूरत है कि जब हरियाणा सरकार गेहूं व धान समेत 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद सकती है तो पंजाब सरकार सिर्फ दो ही फसलों को क्यों खरीद पा रही है। पंजाब सरकार को सबसे पहले हरियाणा में लागू किसान हित की योजनाओं को अपने राज्य में लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मांग को पूरा कराने के लिए किसान संगठनों का आंदोलन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। दिल्ली पहुंचने के बहुत से तरीके हैं। किसान संगठन बसों से, अपनी गाड़ियों से और रेलगाड़ी से भी दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टरों के माध्यम से और वह भी एक-एक साल का राशन-पानी लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ना उनके इरादों को संदिग्ध बनाता है। लाल ने कहा कि किसान संगठनों की मंशा और उद्देश्य को भी समझना होगा। पिछले साल किसानों के आंदोलन से पूरा देश प्रताड़ित हो चुका है।

मुख्यमंत्री नीतीश ने 2,133 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा

पटना (हिंस)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार सचिवालय सेवा अंतर्गत 1,333 सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों तथा विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत 228 सहायक प्राध्यापकों एवं 572 व्याख्याताओं सहित कुल 2,133 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी मनीष कुमार, दीपिका कुमारी, जितेंद्र कुमार मंडल, सरिता कुमारी, सुशील कुमार, रूपा कुमारी, नीलम कुमारी तथा व्याख्याता पीयूष कुमार पाठक, शिप्रा भदानी एवं सहायक प्राध्यापक सारिका कुशवाहा को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस कार्यक्रम में 50 अभ्यर्थियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह ने भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू, 17 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल

पटना (हिंस)। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2024 गुरुवार (15 फरवरी) से शुरू हो रही है। 16 लाख 94 हजार 781 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। 23 फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा को लेकर बोर्ड ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं सेंटर के आसपास की सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। बिहार बोर्ड ने इस परीक्षा के लिए 38 जिलों में 1585 केंद्र बनाए हैं। मैट्रिक परीक्षा में 16,94,781 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें सबसे अधिक संख्या छात्राओं का है। इस परीक्षा में 8,22,587 छात्र एवं 8,72,194 छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगी। लड़कों की तुलना में इस बार 49,609 लड़कियां अधिक है। मैट्रिक परीक्षा दो पालियों में आयोजित किया जाएगा। स्टूडेंट्स जूता-मोजा पहन कर एग्जाम में शामिल नहीं हो सकते हैं। प्रथम पाली में शामिल होने वाले परीक्षार्थी पूरी परीक्षा के दौरान प्रथम पाली की परीक्षा में शामिल होंगे तथा द्वितीय पाली में शामिल होने वाले परीक्षार्थी पूरी परीक्षा के दौरान द्वितीय पाली में शामिल होंगे। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन मैथ विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा में पहली पाली 9:30 बजे से 12:45 बजे तक और द्वितीय पाली की परीक्षा दो बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। आनंद किशोर ने बताया कि प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले सेंटर पर प्रवेश कर लेना होगा। 9:30 बजे सुबह की परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को नौ बजे तक सेंटर पर प्रवेश कर लेना होगा। द्वितीय पाली की परीक्षा दो बजे से शुरू होगी। इसके लिए 1:30 बजे तक परीक्षा भवन में प्रवेश करना होगा। लेट होने पर सेंटर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही स्टूडेंट्स को प्रश्न-पत्र पढ़ने और अन्य कामों के लिए बोर्ड ने अलग से 15 मिनट का समय दिया है।

किसानों के रास्ते पर कीलें लगाई जा रही है और ड्रोन से हमला किया जा रहा है : रंधावा

जयपुर (हिंस)। राजस्थान प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने गुरुवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश का किसान अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा किसानों को दबाने के लिए अमानवीय हथकंडे अपनाते हुए गोलियां चलाने व आंसू गैस छोडने जैसे कार्य किए जा रहे हैं तथा ड्रोन से उन पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार से प्रश्न किया कि हमारे लोकतांत्रिक देश में किसी को अपनी बात रखने के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि आज भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा किसानों से उनका यह मौलिक अधिकार भी छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी आंदोलन कर रहे किसानों पर भाजपा ने अनेकों झूठे लांछन लगाकर बदनाम करने का कार्य किया गया था। आज भी आंदोलन कर रहे किसानों पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं जिसका हम सभी देशवासी विरोध करते हैं। राजस्थान प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने कहा कि आज केंद्र सरकार द्वारा देश के अन्नदाता के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में किसानों को अपनी बात रखने के अधिकार से भाजपा की केंद्र सरकार वंचित करना चाहती है। इसलिये किसानों के रास्ते पर कीलें लगाई जा रही है, ड्रोन से हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के पश्चात् केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी ने दो साल में कोई निर्णय नहीं किया। जिस कारण मजबूर होकर किसान अपनी मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ केंद्र सरकार द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि देश की नई पीढ़ी को यह जानकारी नहीं है कि आजादी से पूर्व देश के बाहर से अनाज लाया जाता था तथा प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस सरकार के अथक प्रयास से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रथम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली गई तथा अनेक नवाचार किए गये जिसके परिणामस्वरूप किसानों की उपज में बढ़ोत्तरी हुई एवं देश कृषि में आत्मनिर्भर हुआ। उन्होंने

कहा कि यूपीए सरकार के शासन में किसानों को 120 प्रतिशत की वृद्धि आय में हुई जबकि वर्तमान एनडीए सरकार के शासन में 50 प्रतिशत की वृद्धि भी नहीं हुई और उर्वरक, कृषि उपकरण, डीजल इत्यादि के दाम बेतहाशा बढ़ गये हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए कोई कार्य नहीं किया बल्कि इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि यूपीए शासन के दौरान स्वामी नाथन् आयोग की रिपोर्ट में वर्णित 200 में से करीब 170 सिफारिशें तत्कालीन यूपीए सरकार ने लागू की थी किन्तु भाजपा की वर्तमान केंद्र सरकार ने शेष रहीं सिफारिशों पर कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार 15 लाख करोड़ रुपए का बड़े उद्योगपतियों का ऋण माफ कर सकती है लेकिन किसानों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि देश के अन्नदाता को अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है जबकि मात्र 500 रुपए महिना किसान सम्मान निधि के रूप में देकर भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन पूरे देश के अन्नदाताओं का आंदोलन है, भले ही इसमें पहल पंजाब ने की हो। उन्होंने कहा कि आज किसान आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है तथा किसानों के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध आज कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार को ड्रोन से हमला, आंसू गैस आदि का प्रयोग देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए करना चाहिए ना कि देश के अन्नदाताओं के विरुद्ध। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लालबहादुर शास्त्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था, जय जवान-जय किसान, क्योंकि यदि देश का किसान एवं जवान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा।

भाकियू चढ़ूनी गुट ने किसानों के समर्थन में किया बड़ा एलान

यमुनानगर (हिंस)। दिल्ली कूच किसान आंदोलन के समर्थन में अब हरियाणा के किसान संगठन भी समर्थन में आगे आने लगे है। इसी कड़ी में गुरुवार को भाकियू चढ़ूनी गुट की प्रदेश स्तरीय कुरुक्षेत्र में एक बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा में भी प्रदेश स्तर पर आंदोलन के समर्थन का एलान कर दिया। भाकियू चढ़ूनी के जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना ने बताया कि शंभू बॉर्डर पर बैठे पंजाब के किसानों को लेकर आज की कुरुक्षेत्र में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार शंभू बॉर्डर पर किसानों पर आंसू गैस और गोलियां बरसाने का काम कर रही है। इन किसानों के लिए हमारा समर्थन है और इसको लेकर कल प्रदेश भर के टोल प्लाजा पर दोपहर 3 घंटे के लिए टोल फ्री कराया जाएगा और 17 17 फरवरी को तहसील स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। यदि उसके बाद भी अगर सरकार हमारी बात पर नहीं मानी तो 18 फरवरी को कुरुक्षेत्र में एक विशाल महापंचायत की जाएगी। जिसमें सभी किसान संगठन के अलावा मजदूर, कर्मचारी, पंचायतें और खापें हिस्सा लेंगी। उसके बाद जो भी आगे निर्णय होगा वह प्रदेश स्तर पर लिया जाएगा और किसान को समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिल्ली में भी पहले हमारे आंदोलन के दौरान मांगों को नहीं माना और आज भी सरकार नही मान रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को एमएसपी देने का वायदा किया था। उन्होंने कहा कि शंभू बॉर्डर पर किसानों पर हरियाणा सरकार द्वारा गोलियां चलाई जा रही है, आंसू गैस छोड़ जा रहे हैं। यह एक तरह की लोकतंत्र की हत्या है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं।

राज्यसभा के लिए भाजपा के सुभाष बराला ने किया नामांकन

चंडीगढ़ (हिंस)। हरियाणा से राज्यसभा की इकलौती सीट पर भाजपा उम्मीदवार सुभाष बराला निर्विरोध निर्वाचित होंगे। गुरुवार को नामांकन करने के आखिरी दिन भाजपा उम्मीदवार सुभाष बराला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस या अन्य किसी दल की ओर से कोई उम्मीदवार ने इस चुनाव के लिए अपना नामांकन नहीं किया। ऐसे में नामांकन वापसी के अंतिम दिन यानी 20 फरवरी को सुभाष बराला को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। दरअसल, भाजपा के डीपी वत्स का कार्यकाल पूरा होने बाद राज्यसभा सीट रिक्त होने जा रही है।

50 के करीब लोगों ने थामा पीडीपी का दामन

आरएस पुरा (हिंस)। पीडीपी की तरफ से आरएस पुरा क्षेत्र के गांव कोटली शाह दुल्ला में गुरूवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में लोग अन्य राजनीतिक दल छोड़कर पीडीपी में शामिल हो गए। उनका पार्टी के जिला ग्रामीण प्रधान केके शर्मा तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र शर्मा की तरफ से हार पहना कर स्वागत किया गया। इससे पहले क्षेत्र में पहुंचने पर पीडीपी के जिला ग्रामीण प्रधान के.के शर्मा का पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष बनने के बाद उनका क्षेत्र का पहला दौरा था। इस मौके पर पार्टी में शामिल होने वाले लोगों का स्वागत करते हुए पीडीपी के जिला ग्रामीण प्रधान केके शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पीडीपी में ज्यादा से ज्यादा लोगों का शामिल होना इस बात को साबित करता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में पीडीपी जम्मू कश्मीर की सभी लोकसभा सीट पर जीत हासिल करेगी और विधानसभा चुनाव में भी पार्टी जीत हासिल कर जम्मू-कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा हर चुनाव में लोगों को धर्म तथा क्षेत्रवाद को लेकर राजनीति करती है लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर की जनता समझ चुकी है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी ही एक विकल्प के रूप में उभर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पीडीपी की तरफ से लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र शर्मा ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के निर्देशों पर पीडीपी की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज 50 के करीब लोग पीडीपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी ही जम्मू कश्मीर के दोनों संभागों में बेहतर विकास करवा सकती है और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवा सकती है। उन्होंने पार्टी में शामिल होने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा कि वह पार्टी की नीतियों को जन-जन तक लेकर जाएं। इस मौके पर पार्टी के अन्य लोगों ने भी अपने-अपने विचार रखे।

बहुचर्चित भंवरी हत्याकांड

हाईकोर्ट ने पति और अन्य वारिसान को परिलाभ देने के आदेश दिए

जोधपुर (हिंस)। राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ के न्यायाधिपति अरूण मोंगा की अदालत ने भंवरी देवी हत्याकांड में मृतका भंवरी के पति अमरचंद के अलावा भंवरी देवी के अन्य विधिक वारिसान/याचीगण को 01 सितंबर, 2011 से बकाया सेवा परिलाभ और नियमित पेंशन व सेवानिवृत्ति परिलाभ की गणना कर समस्त परिलाभ चार माह के भीतर भीतर देने के आदेश जारी किए है। न्यायाधिपति की ओर से समस्त परिलाभ व एरियर पर बकाया होने की दिनांक से नियमानुसार ब्याज की गणना कर दिए जाने के भी निर्देश दिए गए है। आदेश में कहा गया कि पति अमरचंद के हिस्से का बकाया पैसा, परिलाभ अंश उसके आपराधिक मामले में बरी होने तक विभाग में ही जमा रहेगा। याचीगण अस्विनी, सुहानी और साहिल पेमावत की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी और विनीता ने पैरवी की।

गठबंधन की सरकार के भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने के लिए न्याय चाहिए : सुदेश महतो

रांची (हिंस)। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि गठबंधन की सरकार के भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने के लिए न्याय चाहिए। सत्तारूढ़ दल अन्याय करने के लिए न्याय यात्रा पर निकला है। इन्होंने पूरे देश में राज्य के परिचय को बदल कर साख को खराब किया है। कोयला, पत्थर, बालू जैसे खनिज संपदा को बेचने वाली यह सरकार अब युवाओं की नौकरी भी बेच रही है। महतो गुरुवार को केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश महासचिव निकेश कुमार लाल और पार्टी के केंद्रीय सदस्य अभिरंजन तिवारी के नेतृत्व में कई युवाओं और बुद्धिजीवियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही एप्सेंसिस ग्रुप के निदेशक और सीईओ मनीष कुमार पांडेय ने पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थामा। पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों का स्वागत करते हुए सुदेश कुमार महतो ने कहा कि आप सभी को सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए राजनीतिक दायित्व और जवाबदेही को निभाना होगा। अलग-अलग पेशे के लोग आजसू से जुड़ रहे हैं। युवाओं के राजनीति में आने से अच्छा माहौल पूरे प्रदेश में विकसित हो रहा है। यह एक बड़े विचार को खड़ा करेगा। आने वाले समय में आजसू पार्टी का दायित्व बढ़ने वाला है। हमने हर विचार को जगह देने का काम किया है। राजनीति थोपी हुई विचारों से नहीं चलती है। आम विचारों को नेतृत्व करने वाली पार्टी आजसू है। निकेश कुमार लाल ने कहा कि सुदेश महतो के विचारों से पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूं। राज्य की परिस्थिति और जनता की सेवा के लिए आज आजसू पार्टी में शामिल हो रहा हूं। आजसू पार्टी जो भी कार्य करने का निर्देश देगी उसका हम पालन करेंगे। राज्य को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए सुदेश महतो के नेतृत्व की आवश्यकता है। मिलन समारोह को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता प्राची नारायण, युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार सिन्हा, प्रो. दीपक कुमार गुप्ता, रेखा सिन्हा और मनीष कुमार पांडे ने भी संबोधित किया।

नंदकिशोर यादव बने बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष

पटना (हिंस)। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद गुरुवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद नंदकिशोर यादव को सर्वसम्मति से स्पीकर चुना गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नए स्पीकर को आसन पर बैठाया। तेजस्वी ने सदन में नंदकिशोर यादव का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बिहार में राजग की सरकार के गठन के बाद पुरानी महागठबंधन की सरकार में विधानसभा के स्पीकर रहे अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ सदन में अविस्वास प्रस्ताव लाया गया था। स्पीकर के पद से हटाए जाने के बाद नंदकिशोर यादव ने विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद उन्हें निर्विरोध विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। विधानसभा में स्पीकर के तौर पर नंद किशोर यादव के पक्ष में 15 प्रस्ताव आए जबकि विपक्ष में किसी अन्य ने प्रस्ताव नहीं दिया। इसके बाद सर्वसम्मति से नंदकिशोर यादव 2020 से 2025 तक के लिए तीसरे स्पीकर के रूप में चुन लिए गए।

हिट एंड रन कानून के विरोध में रोडवेज कर्मियों ने बैठक कर बनाई हड़ताल की रणनीति

कैथल (हिंस)। संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए सीआईटीयू से संबद्ध दी ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के बैनर तले गुरुवार को रोडवेज कर्मचारियों ने प्रधान जसबीर सिंह की अध्यक्षता में बैठक कर बस अड्डे पर धरना दिया। यूनियन नेता जसबीर सिंह, रामपाल राविश, विजेंद्र सारण व राकेश शर्मा ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता में बनाया गया हिट एंड रन कानून केवल ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं बल्कि सभी बस, कार, कैंटर, पिकअप, टेक्सी, टेम्पू, जीप, थ्रीव्हीलर, ई-रिक्शा समेत सभी निजी वाहन चलाने वालों पर भी लागू होगा। यंहा तक कि दो पहिया वाहन स्कूटर, मोटर साईकिल, स्कूटी चलाने वाले पुरुष व महिला भी इस कानून की जद में आएंगे। राज्य कैशियर जसबीर सिंह ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने यह कानून विपक्ष के 146 सांसदों को ससपेंड कर बिना किसी चर्चा के बनाए हैं। ड्राइवर्स के साथ पहले ही पुलिस व परिवहन अधिकारियों द्वारा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इस नए कानून से तो ज्यादतियां व भृष्टाचार और ज्यादा बढ़ेगा। यही नहीं, इस कानून से पहले 2019 में भी सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राईवर पर चालान के रूप में भारी जुर्माने थोंपे गए थे। परंतु सरकार दुर्घटना के असल कारणों से लगातार मुंह मोड़ रही है। सड़कों की कम चौड़ाई, रखरखाव, पृथकीकरण व उन पर लाईट की व्यवस्था इत्यादि की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। परंतु वह अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते हुए सारा दोष ड्राइवर्स पर मढ़ रही है। क्योंकि रखरखाव का सारा काम प्राइवेट कम्पनियों के हवाले कर रखा है। जिनका ध्यान सड़कों की बेहतरी की बजाए टोल वसूलने पर ही ज्यादा रहता है। इसलिए सरकार ईमानदारी से यदि दुर्घटनाओं को रोकना व कम करना चाहती है तो अकेले ड्राइवर्स को दंडित करने की बजाए वास्तविक कारणों की पहचान कर उन समस्याओं का समाधान करें। इसलिए सीटू मांग करता है कि काले कानूनों को वापिस लिया जाए।

राजस्थान के 88 हजार स्कूलों के 1.14 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार कर बनाया विश्व कीर्तिमान

जयपुर (हिंस)। सूर्य सप्तमी के अवसर पर राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में गुरुवार को आयोजित सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित 1.33 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी निभाते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस विश्व रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन के राजस्थान एडिशन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस विशिष्ट उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे सफल बनाने में सहभागिता निभाने वाले प्रदेश के स्कूलों के विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, संस्था प्रधानों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का आभार जताया है। उन्होंने इस आयोजन के सुव्यवस्थित प्रबंधन में सजगता और जिम्मेदारी से भूमिका निभाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन के वाइस प्रेसिडेंट राजस्थान प्रथम भल्ला ने इस विश्व रिकॉर्ड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट गुरुवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में भेंट किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक अविचल चतुर्वेदी, स्कूल शिक्षा विभाग की विशिष्ट शासन सचिव चित्रा गुप्ता, माध्यमिक शिक्षा निदेशक

आशीष मोदी और उप निदेशक शाला दर्पण तूलिका गर्ग सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि पूरे प्रदेश के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में गुरुवार को प्रात: 10.30 बजे से 11 बजे की अवधि में एक ही समय पर एक साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया गया। इसमें 88 हजार 974 स्कूलों के एक करोड़ 14 लाख 69 हजार 914 विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार किया। वहीं विद्यार्थियों सहित कुल एक करोड़ 33 लाख 50 हजार 889 लोग इन आयोजनों में शामिल हुए। विद्यार्थियों के अलावा शिक्षा विभाग के कार्मिक, जन प्रतिनिधि, अभिभावक, अधिकारीगण और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने इसमें भागीदारी की। उन्होंने बताया कि प्रदेश कि 66 हजार 990 सरकारी स्कूलों में 64 लाख 30 हजार 277 तथा 21 हजार 984 गैर सरकारी स्कूलों के 50 लाख 39 हजार 637 विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार किया। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों सहित 77 लाख 63 हजार 374 तथा गैर सरकारी स्कूलों में 55 लाख 87 हजार 515 लोग इन आयोजनों में शामिल हुए।

केंद्र ने डेयरी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने को 29,610 करोड़ की योजना शुरू की

नई दिल्ली।
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने 29,610 करोड़ रुपये की पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजना शुरू की। मंत्री ने कहा कि कोविड काल के दौरान शुरू की गई योजना को नया स्वरूप दिया गया है। इसे अगले 3 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। उद्योग, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और डेयरी सहकारी समितियों को इस योजना से लाभ होगा क्योंकि परिव्यय पहले के 15,000 करोड़ रुपये से दोगुना होकर 29,610 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 फरवरी को अपनी बैठक में 29,610 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत एएचआईडीएफ के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी, जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत आवंटित 15,000 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना है, जिसे योजना में शामिल किया गया है। डेयरी सहकारी समितियों को अब एएचआईडीएफ के तहत डीआईडीएफ में मिलने वाली 2.5 प्रतिशत की बजाय 3 प्रतिशत की ब्याज छूट का लाभ मिलेगा। डेयरी सहकारी को एएचआईडीएफ के क्रेडिट गारंटी फंड के तहत क्रेडिट गारंटी सहायता भी मिलेगी। मंत्री ने कहा कि यह योजना डेयरी सहकारी समितियों को अद्यतन प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के साथ अपने प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने में मदद करेगी। इससे देश में बड़ी संख्या में दूध उत्पादकों को फायदा होगा। उद्घाटन समारोह में उद्योग संघ, एनडीडीबी, डेयरी सहकारी समितियां, एफपीओ और पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारी मौजूद थे। बातचीत के दौरान पात्र संस्थाओं में से एक, एबीआईएस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने पशुधन क्षेत्र में बुनियादी ढांचा बनाने में योजना की भूमिका की सराहना की और कहा कि वे बुनियादी ढांचे के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।

योजना की मुख्य बातें...

- 1- क्रेडिट गारंटी टर्म लोन के 25 प्रतिशत तक कवर करती है।
- 2- ऋण राशि की कोई सीमा नहीं है।
- 3- अनुमानित/वास्तविक परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक ऋण।
- 4- अन्य मंत्रालयों या राज्य स्तरीय योजनाओं की पूंजीगत सब्सिडी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाना।
- 5- ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन प्रक्रिया में आसानी।

न्यूज ब्रीफ

जापान को पछाड़कर जर्मनी बना तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली। जर्मनी 2023 में जापान के पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के खुदरा अनुसंधान प्रमुख दीपक जसानी ने यह बात कही।उन्होंने कहा कि जापान का नॉमिनल जीडीपी पिछले साल कुल 4.2 लाख करोड़ डॉलर या लगभग 591 लाख करोड़ येन था। पिछले महीने घोषित जर्मनी का जीडीपी 4.4 लाख करोड़ डॉलर से 4.5 लाख करोड़ डॉलर के बीच था। वास्तविक जीडीपी पर कैबिनेट कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, नवीनतम अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में साल-दर- साल आधार पर जापानी अर्थव्यवस्था में 0.4 प्रतिशत का संकुचन रहा। पूरे साल के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में 1.9 प्रतिशत बढ़ गया। इससे पहले जुलाई-सितंबर तिमाही में 3.3 प्रतिशत संकुचन रहा था। उन्होंने कहा कि लगातार दो तिमाहियों में संकुचन को व्यापक रूप से तकनीकी मंदी माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, जापान की अर्थव्यवस्था लगातार दो तिमाहियों तक सिकुड़ने के बाद अप्रत्याशित रूप से मंदी की चपेट में आ गई है। देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2023 के आखिरी तीन महीनों में एक साल पहले की तुलना में उम्मीद से ज्यादा 0.4 प्रतिशत घट गया। रिपोर्ट के अनुसार, जापान के कैबिनेट कार्यालय के आंकड़े यह भी संकेत देते हैं कि देश ने जर्मनी के हाथों दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का अपना स्थान भी खो दिया है। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद थी कि नए आंकड़ों से पता चलेगा कि पिछले साल की चौथी तिमाही में जापान की जीडीपी 1 प्रतिशत से अधिक बढ़ी। अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अनुमान लगाया था कि अमेरिकी डॉलर में मापने पर जर्मनी के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान से आगे निकलने की संभावना है। आईएमएफ अपनी रैंकिंग में बदलाव की घोषणा तभी करेगा जब दोनों देश अपने आर्थिक विकास के आंकड़ों के अंतिम संस्करण प्रकाशित कर देंगे।

क्या होते हैं चुनावी बॉन्ड, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने 2024 के आम चुनावों से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर अपना निर्णायक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगा दी है। क्या होते हैं चुनावी बॉन्ड देश में कब और क्यों लाया गया चुनावी बॉन्ड क्या इसमें पैसे लगाने पर मिलता है रिटर्न आम जनमानस के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड से जुड़े कई सवाल हैं आइए उनके जवाब जानते हैं। क्या है चुनावी बॉन्ड चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र है। इसकी खरीदारी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी की ओर से की जा सकती है। यह बॉन्ड नागरिक या कॉरपोरेट कंपनियों की ओर से अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को दान करने जरिया है। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत कब हुई चुनावी बॉन्ड को फाइनेंशियल (वित्तीय) बिल (2017) के साथ पेश किया गया था। 29 जनवरी, 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया था। उसी दिन से इसकी शुरुआत हुई कब-कब बिक्री के लिए मुहैया होता था चुनावी बॉन्ड चुनावी बॉन्ड हर तिमाही की शुरुआत में सरकार की ओर से 10 दिनों की अवधि के लिए बिकी के लिए उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। इसी बीच उनकी खरीदारी की जाती थी। सरकार की ओर से चुनावी बॉन्ड की खरीद के लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 दिन तय किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के वर्ष में सरकार की ओर से 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि तय किए जाने का प्लान था। चुनावी बॉन्ड का मकसद क्या था चुनावी बॉन्ड की शुरुआत करते हुए सरकार ने दावा किया था इससे राजनीतिक फंडिंग के मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस बॉन्ड के जरिए अपनी पसंद की पार्टी को चंदा दिया जा सकता था। चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक दलों को कैसे मिलता था लाभ कोई भी भारतीय नागरिक, कॉरपोरेट और अन्य संस्थाएं चुनावी बॉन्ड खरीद सकते थे और राजनीतिक पार्टियां इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल कर लेते थे। बैंक चुनावी बॉन्ड उसी ग्राहक को बेचते थे, जिनका केवाईसी वेरिफाइड होता था। बॉन्ड पर चंदा देने वाले के नाम का जिक्र नहीं होता था। क्या चुनावी बॉन्ड में निवेश करने पर कुछ रिटर्न मिलता है। चुनावी बॉन्ड में निवेश करने वाले को आधिकारिक तौर पर कोई रिटर्न नहीं मिलता था। यह बॉन्ड एक रसीद के समान था। आप जिस पार्टी को चंदा देना चाहते हैं, उसके नाम से इस बॉन्ड को खरीदा जाता था और इसका पैसा संबंधित राजनीतिक दल मुहैया

भारतीय और चाइनीज कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा यूरोपीय संघ, रूस की मदद करने का आरोप

जर्मनी।
यूरोपीय संघ भारतीय-चाइनीज समेत कई अन्य देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। यूरोपीय संघ का आरोप है कि ये कंपनियां यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद कर रही हैं। यूरोपीय संघ ने इन कंपनियों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव दिया है और अगर ये प्रस्ताव सभी सदस्य देश पारित कर देते हैं तो ये पहली बार होगा, जब चीन की कंपनी पर यूरोपीय संघ सीधा प्रतिबंध लगाएगा।

यूरोपीय कंपनियों के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगी प्रतिबंधित कंपनियां

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूरोपीय संघ जिन कंपनियों पर प्रतिबंध की तैयारी कर रहा है, उनमें हॉन्ग-कॉन्ग, सर्बिया, भारत, तुर्किए और चीन की कंपनियां शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह खबर सामने आयी है। हालांकि कानूनी कारणों से कंपनियों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है।

कंपनियों पर प्रतिबंध का मतलब ये होगा कि जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगेगा, वो भविष्य में यूरोप की कंपनियों के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगी। यूरोपीय संघ का आरोप है कि रूस इन्हीं थर्ट पार्टी कंपनियों की मदद से प्रतिबंधित सामान की खरीद कर रहा है, जो प्रतिबंधों की वजह से उसे सीधे नहीं मिल पा रहा है।

चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने से हिचकिचा रहा यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद के आरोप में पहले भी कई चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वह प्रस्ताव कई सदस्य देशों के विरोध के बाद खारिज कर दिया गया था। साथ ही चीन ने भी वादा किया था कि वह रूस की मदद नहीं करेगा। बता दें कि चीन, यूरोप के कई देशों का अहम व्यापारिक साझेदार है। यूरोपीय संघ के प्रमुख देश जर्मनी की कारों के लिए चीन की सबसे बड़ा बाजार है। यही वजह है कि यूरोपीय संघ के कई देश चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने से हिचकिचा रहे हैं।

जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है, उनमें अधिकतर कंपनियां तकनीकी और इलेक्ट्रोनिक्स कंपनियां हैं। कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने रूस के सैन्य और तकनीकी तौर पर मजबूत होने में मदद की और रूस के रक्षा और सुरक्षा सेक्टर के विकास में योगदान दिया। बीते साल अप्रैल में यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लिन ने बीजिंग का दौरा किया था और उस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी चिंताओं से उन्हें अवगत कराया था। यूरोपीय संघ जिन कंपनियों पर प्रतिबंध की तैयारी कर रहा है, उनमें तीन कंपनियां चाइनीज, एक भारतीय, एक श्रीलंकाई, सर्बिया, कजाखस्तान, थाईलैंड, तुर्किए और हॉन्ग कॉन्ग की कंपनियां शामिल हैं।

कोयला गैसीकरण परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए हैदराबाद में उद्योग बैठक आयोजित कर रहा केंद्र

नई दिल्ली।
केंद्रीय कोयला मंत्रालय हैदराबाद में एक उद्योग संवाद की मेजबानी करेगा, इसका उद्देश्य देश भर में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के विकास में तेजी लाना है। कोयला मंत्रालय ने कहा कि यह आयोजन भारत में टिकाऊ ऊर्जा समाधान चलाने के लिए कोयले और लिग्नाइट संसाधनों की क्षमता का दोहन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार ने देश की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 8,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।

गैसीकरण परियोजनाओं की योजना तीन श्रेणियों के तहत बनाई गई है, इसमें सरकारी पीएसयू व निजी खिलाड़ियों के साथ-साथ छोटे पैमाने की परियोजनाएं भी शामिल हैं। कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने, आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। आधिकारिक बयान के अनुसार, कोयला मंत्रालय का लक्ष्य उद्योग हितधारकों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र के भीतर नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देकर गैसीकरण प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाना है। यह आयोजन कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं से जुड़े अवसरों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा। प्रतिभागियों से भारत में गैसीकरण पहल के विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक चर्चाओं में शामिल होने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सहयोग के रास्ते तलाशने की उम्मीद की जाती है। कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीना इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, इसमें कोल इंडिया के अध्यक्ष पी.एम. प्रसाद भी शामिल होंगे।

जनवरी 2024 में व्यापार घाटा कम हुआ, निर्यात में सालाना आधार पर 3 प्रतिशत का इजाफा

नई दिल्ली ।
जनवरी में भारत का व्यापारिक व्यापार घाटा घटकर 17.49 अरब डॉलर हो गया क्योंकि लाल सागर में चल रहे संकट के बावजूद निर्यात में सालाना आधार पर 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिसंबर 2023 में मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट 19.80 अरब डॉलर था बिलियन था 15 फरवरी को वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 2024 के पहले महीने में भारत का निर्यात 36.92 बिलियन डॉलर था। यह जनवरी 2023 के 35.80 बिलियन डॉलर से अधिक है, लेकिन दिसंबर 2023 के 38.45 बिलियन डॉलर से कम है। वाणिज्य सचिव सुनील कुमार बर्थवाल ने कहा कि लाल सागर में हौती विद्रोहियों के हमलों, विकसित देशों में जारी मंदी और कॉमोडिटिज की कीमतों में गिरावट के बावजूद हम अपने निर्यात के आंकड़े सुधारने में सफल रहे हैं।

सोने और चांदी की कीमतो में आई भारी गिरावट

नई दिल्ली ।
घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतें नीचे आई हैं। इन दोनो ही कीमती धातुओं के वायदा भाव बढ़त पर खुले पर बाद में इनमें गिरावट देखी गयी। सोने के वायदा भाव की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। वहीं चांदी के वायदा भाव 70 हजार रुपये पर कारोबार कर रहे थे। गत दिवस इसके भाव टूटकर 70 हजार से नीचे चले गए थे। वहीं सोने के वायदा भाव 61,300 रुपये के करीब कारोबार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी के वायदा भाव तेजी के साथ खुले पर सोने की कीमतें तेज शुरुआत के बाद नीचे आयीं।

भाव तेज शुरुआत के बाद फिसल गए। सोने के वायदा भाव की शुरुआत कमजोर रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अप्रैल अनुबंध 36 रुपये नीचे आकर 61,407 रुपये पर खुला। ये 61,412 रुपये के भाव पर दिन के उच्च स्तर और 61,284 रुपये के भाव पर दिन के निचले स्तर पर पहुंचा। पिछले साल दिसंबर माह में सोने के वायदा भाव 64,063 रुपये के शीर्ष स्तर पर पहुंचे थे। वहीं चांदी के वायदा भाव की शुरूआत बढ़त पर हुई।

एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क मार्च अनुबंध 148 रुपये की तेजी के साथ 70,300 रुपये के भाव पर खुला। ये 70,383 रुपये के भाव पर दिन के उच्च और 70,050 रुपये प्रति किलो के भाव पर दिन का निचला स्तर पर पहुंचा। वहीं पिछले साल दिसंबर महीने में चांदी के वायदा भाव 78,549 रुपये किलो के भाव पर पहुंच गए थे।

वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी के वायदा भाव बढ़त पर खुले। कामेक्स पर सोना 2,004.80 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। वहीं पिछला बंद भाव 2,004.30 डॉलर था। दूसरी ओर कामेक्स पर चांदी के वायदा भाव 22.42 डॉलर के भाव पर खुले। इनका पिछला बंद भाव 22.39 डॉलर था।

ईडी ने पेटीएम के अधिकारियों से की पूछताछ; दस्तावेज लिए, गड़बड़ी मिली तो फेमा के तहत होगी जांच

नई दिल्ली ।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक के खाते में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोकने की भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया कार्रवाई के बाद पेटीएम के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की और उनसे दस्तावेज जमा करवाए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी आरबीआई द्वारा चिह्नित फिनटेक कंपनी में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कथित अनियमितताओं की औपचारिक जांच शुरू करने का निर्णय लेने से पहले दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच कर रही है।

पेटीएम के अधिकारियों ने हाल ही में कुछ दस्तावेज जमा कराए हैं, जिसके बाद उनसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। सूत्रों ने बताया कि कुछ और जानकारी मांगी गई है। सूत्रों के अनुसार अब तक किसी अनियमितता का पता नहीं चला है और उक्त कानून के तहत किसी तरह का उल्लंघन पाए जाने पर ही फेमा के तहत सूत्रों ने बताया कि पेटीएम से जुड़े धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुछ समय से जांच चल रही है। पेटीएम ब्रांड के तहत वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस और उसकी बैंकिंग इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नोटिस जारी कर संबंधित इकाइयों के ग्राहकों के संबंध में जानकारी देने को कहा गया है। पेटीएम ने कहा कि उसकी सहयोगी पेटीएम पेमेंट बैंक विदेश से धन प्रेषण का कारोबार नहीं करती है।

उधर, पेटीएम ने एक नियामक फाइलिंग में कहा है कि वन 97 उसकी सहायक कंपनियां और उसकी सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को संबंधित संस्थाओं के साथ कारोबार करने वाले ग्राहकों के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित अधिकारियों से सूचना, दस्तावेज और स्पष्टीकरण के लिए समय-समय पर नोटिस और डिमांड प्राप्त होती रही है, और अधिकारियों को आवश्यक जानकारी, दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रदान किए गए हैं। पेटीएम ने कहा कि कंपनी और उसकी सहयोगी अधिकारियों को आवश्यकतानुसार जानकारी, दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रदान कर रहे हैं।

निदेशालय और वित्तीय खुफिया इकाई ने आरबीआई से पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को ग्राहक खातों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोकने की हालिया कार्रवाई पर अपनी रिपोर्ट साझा जनवरी को उसे निर्देश दिया था कि वह 29 फरवरी के बाद किसी भी ग्राहक खातों, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना बंद कर दे। ईडी चीनी नियंत्रित लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में पेटीएम और अन्य ऑनलाइन भुगतान वॉलेट की जांच कर रहा है, जिन्होंने कथित तौर पर इन फिनटेक प्लेटफार्मों पर बनाए गए मर्चेंट आईडी का उपयोग करके धन

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आया बदलाव

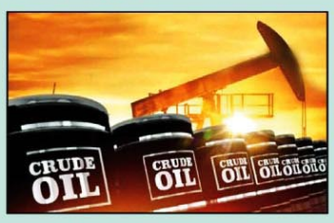

नई दिल्ली । घरेलू बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव आया है। दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच ही बाजार में तेल की कीमतें भी प्रभावित हुई हैं। दुनिया भर के बाजारों में भी कच्चे तेल की कीमतों में करीब 1 डॉलर की कमी आई है। उत्तरप्रदेश के कई शहरों में तेल महंगा हुआ, जबकि बिहार में कीमतें गिरी हैं। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार, गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल की कीमतें 42 पैसे बढ़कर 97.00 रुपये प्रति लीटर हो गयी हैं। यहां डीजल भी 39 पैसे महंगा होकर 90.14 रुपये लीटर पहुंच गया। वहीं लखनऊ में पेट्रोल 10 पैसे नीचे आकर 96.47 रुपये लीटर जबकि डीजल 10 पैसे टूटकर 89.66 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमतें 56 पैसे कम हुई हैं। यह 107.24 रुपये लीटर पहुंच गया है जबकि डीजल 52 पैसे गिरावट के साथ 94.04 रुपये लीटर बिक रहा है। वहीं दुनिया भर के बाजारों में कच्चा तेल सस्ता हुआ है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें एक डॉलर नीचे आकर 81.60 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गयी हैं। वहीं डब्ल्यूटीआई के दाम भी गिरावट के साथ 76.43 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गये हैं। चारों की महानगरों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर, मुंबई पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई पेट्रोल 102.63 रुपये और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर, नोएडा में पेट्रोल 97.00 रुपये और डीजल 90.14 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है।

भारत ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल हंगरी को सौंपी, खेल मंत्री अनुराग और आनंद का दिलचस्प अंदाज

नई दिल्ली ।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड की मशाल इसके 45वें संस्करण के आधिकारिक मेजबान हंगरी को सौंपी। भारत ने चेन्नई में 2022 में चेस ओलंपियाड की मेजबानी की थी और पहली बार इसकी मशाल देश के 75 शहरों में निकाली थी। इसी मशाल को खेल मंत्री ने शतरंज की शीर्ष वैश्विक संस्था फिडे के अध्यक्ष आर्केडी ड्वारकोविच और दुनिया की शीर्ष महिला ग्रैंड मास्टर रहीं जूडिथ पोल्गर को सौंपी। इस मौके पर पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद और भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष संजय कपूर भी मौजूद रहे।

शतरंज खेल नहीं एक बौद्धिक विरासत

खेल मंत्री ने इस मौके पर विश्वनाथन आनंद के साथ मिलकर ड्वारकोविच और जूडिथ पोल्गर के खिलाफ दोस्ताना शतरंज की बाजी भी खेली। खेल मंत्री ने इस मौके पर कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने शतरंज ओलंपियाड की मशाल निकालने का जो फैसला लिया था, वह वास्तव में मशाल हैंडऑफ समारोह के साथ संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि शतरंज एक बौद्धिक विरासत है, जो संभवत: भारत ने दुनिया को प्रदान की है। यह खेल मात्र नहीं बल्कि रणनीतिक गहराई और दार्शनिक ज्ञान का प्रतिङ्क्षबब है।

बुडापेस्ट में होना शतरंज ओलंपियाड

चेन्नई में हुए 44वें शतरंज ओलंपियाड में ढाई हजार से अधिक खिलाड़ियों ने शिरकत की। अगला चेस ओलंपियाड फिडे की ओर से बुडापेस्ट (हंगरी) में कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून, 2022 को प्रथम शतरंज ओलंपियाड मशाल की शुरुआत की थी। भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष संजय कपूर ने कहा कि शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी किसी सपने के सच होने जैसा है। मेजबान टीम के इस ओलंपियाड में प्रदर्शन ने भारतीय शतरंज में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की।

न्यूज ब्रीफ

स्वीयाटेक लगातार तीसरी बार दोहा क्वार्टरफाइनल में

दोहा। विश्व नंबर 1 इगा स्वीयाटेक ने राउंड 16 में नंबर 14 वरीयता प्राप्त एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा को 6-1, 6-4 से हराकर कतर ओपन में अपनी प्रभावशाली जीत का सिलसिला आगे बढ़ाया और लगातार तीसरी बार इस टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में पहुंच गईं। दो बार के डिफेंडिंग चैंपियन स्वीयाटेक ने 1 घंटे और 31 मिनट की जीत के साथ अलेक्जेंड्रोवा को हराकर टूर्नामेंट में अब लगातार 10 मैच जीते हैं। पोल अब क्वार्टर फाइनल में दो बार की दोहा चैंपियन विक्टोरिया अजारेंका से खेलेंगी। पूर्व विश्व नंबर 1 अजारेंका ने रात के मैच में नंबर 8 वरीयता प्राप्त जेलेना ओस्टापेंको को 6-0, 6-3 से हराया, जो इस साल ओस्टापेंको पर उनकी तीसरी जीत है। वर्ल्ड नंबर-19 अलेक्जेंड्रोवा को हराकर, स्वीयाटेक ने शीर्ष 20 विरोधियों के खिलाफ अपने पिछले 11 मैच जीते हैं, और इस साल अब तक उस समूह के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 4-0 पहुंचा दिया है। डब्ल्यूटीए के अनुसार, स्वीयाटेक की शीर्ष 20 के किसी साथी सदस्य से आखिरी हार पिछले सितंबर में टोक्यो क्वार्टर फाइनल में वेरोनिका कुडरमेतोवा से हुई थी। इससे पहले पूर्व विश्व नंबर 1 नाओमी ओसाका क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं, जब राउंड 16 की उनकी प्रतिद्वंद्वी, विश्व नंबर 37 लेसिया सुरेंको कोहनी की चोट के कारण मैच से हट गईं। ओसाका, जो 2022 के अंत और पूरे 2023 तक मातृत्व अवकाश पर थी, 2022 के मार्च में मियामी ओपन फाइनल में पहुंचने के बाद से अपने पहले डब्ल्यूटीए टूर क्वार्टर फाइनल में है। क्वार्टर फाइनल में, दो बार की डब्ल्यूटीए 1000 टाइटलिस्ट ओसाका का सामना एक अन्य पूर्व विश्व नंबर 1, कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा, जिन्होंने अपनी साथी चेक लिंडा नोस्कोवा को तीन सेटों में 3-6, 7-5, 6-1 से हराया।

कतर ओपन से हटे नडाल ने कहा: प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार नहीं हूं

नई दिल्ली। पूर्व विश्व नं. नंबर 1 टेनिस स्टार राफेल नडाल ने आगामी कतर ओपन से हटने के बाद अपने ब्रेक को और बढ़ा दिया है। 22 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता को दोहा में 19 फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करनी थी। लेकिन, 37 वर्षीय ने कहा कि वह दोहा में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। वो लास वेगास में और महीने के अंत में इंडियन वेल्स में कार्लोस अल्काराज के खिलाफ फ्रेंडली मैच पर फोकस कर रहे हैं। स्पैनियार्ड ने एक्स पर लिखा,मैं दोहा में खेलना पसंद करूंगा, जहां टूर्नामेंट टीम के साथ-साथ अद्भुत कतर प्रशंसकों ने हमेशा मेरा बहुत समर्थन किया है। दुर्भाग्य से मैं प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार नहीं हूं और मैं दोहा नहीं आ पाऊंगा । मैं लास वेगास में प्रदर्शनी और इंडियन वेल्स टूर्नामेंट के लिए तैयार रहने के लिए काम करते रहने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। चोट के कारण लगभग एक साल तक बाहर रहने के बाद नडाल ने अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित वापसी जनवरी में ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में की। वह क्वार्टरफाइनल में पहुंच गए लेकिन जॉर्डन थॉम्पसन के खिलाफ मुकाबले के दौरान वो चोटिल हो गए। चोट के कारण नडाल को ग्रैंड स्लैम शुरू होने से एक सप्ताह पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन से हटना पड़ा।

एलसीटी के दूसरे सत्र में न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स की कप्तानी करेंगे युवराज

नई दिल्ली । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह अब अगले माह होने वाले लीजेंड्स लीग क्रिकेट ट्रॉफी (एलसीटी) के दूसरे सत्र में न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स की कप्तानी करते नजर आयेंगे। युवराज को इस सत्र के लिए टीम का कप्तान और आइकन खिलाड़ी घोषित किया गया है। युवराज की इस टीम में कई दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल है। इसमें बाबर आजम, राशिद खान, कीरोन पोलार्ड, इमाम उल हक, नसीम शाह, मथीशा पथिराना, रहमानुल्लाह गुरबाज़, आसिफ अली और मोहम्मद आमिर आदि हैं। न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स फ्रेंचाइजी ने कहा, युवराज के शामिल होने से टीम में विशेषज्ञता, कौशल और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। टूर्नामेंट के आगामी संस्करण में नेतृत्व करने के लिए न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स की तैयारी भी बेहतर होगी। 90 गेंदों के प्रारूप में खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट 7-18 मार्च तक श्रीलंका के कैंडी में खेला जाएगा। 20 ओवर के प्रारूप में खेला गया इसका पहला सत्र पिछले साल 22 से 30 मार्च तक गाजियाबाद में रखा गया था।

मैनचेस्टर सिटी की जीत में डि ब्रुइन बने हीरो रियल मैड्रिड ने लिपजिग को 1-0 से हराया

कोपेनहेगन (डेनमार्क)।
पिंडलियों में खिचाव के कारण पांच माह तक फुटबाल के मैदान से दूर रहने वाले बेल्जियम के स्टार फुटबालर केविन डि ब्रुइन ने मैनचेस्टर सिटी की कोपेनहेगेन पर 3-1 से जीत में मुख्य भूमिका निभाई। चैंपियंस लीग के अंतिम-16 के प्रथण चरण के मुकाबले में डि ब्रुइन ने एक गोल किया और फिल फोडेन की ओर से किए गए तीसरे गोल में भूमिका निभाई। गत विजेता मैनचेस्टर सिटी को अब क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए कोपेनहेगेन के साथ दूसरे चरण के मुकाबले में महज ड्रॉ खेलना होगा। पहले हाफ में 2-1 की बनाई बढ़त खेल के पहले 20 मिनट में सिटी ने अपना पूरा दबदबा बना लिया। इस दौरान 85 प्रतिशत गेंद उनके पास रही। 10वें मिनट में ही डि ब्रुइन ने गोल कर सिटी को 1-0 की बढ़त दिला दी, लेकिन 34वें मिनट में चैंपियंस लीग का अपना पहला मैच खेल रहे मैग्नस मैटसन ने सिटी के रक्षण की गलती का फायदा उठाते हुए कोपेनहेगन को 1-1 की बराबरी दिला दी। स्टापेज समय में बर्नाडो सिल्वा ने गोल कर सिटी को फिर 2-1 से आगे कर दिया। दूसरे हाफ में स्टापेज समय में डि ब्रुइन के पास पर फोडेन ने गोल कर सिटी की 3-1 से जीत पक्की कर दी। सिटी के कोच पेप गॉर्डिओला ने डि ब्रुइन के बारे में कहा कि बड़े खिलाड़ी बड़े मौके पर अपनी छाप छोड़ते हैं। डि ब्रुइन ने कहा कि वह सिर्फ अच्छी फुटबाल खेलने की कोशिश कर रहे थे और इसका मजा ले रहे थे। बता दें कि मैनचेस्टर सिटी 2023 का चैंपियंस लीग का विजेता है। रियल मैड्रिड की जीत 14 बार के यूरोपियन चैंपियन रियल मैड्रिड ने भी चैंपियंस लीग के अंतिम-16 के प्रथम चरण में जीत से शुरुआत की है। रियल ने जर्मनी के क्लब लिपजिग को ब्राहिम सिल्वा के गोल की बदौलत 1-0 से पराजित किया। अब छह मार्च को होने वाले दूसरे चरण के मैच में रियल को क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए ड्रॉ खेलना होगा। ला लिगा के पिछले मैच में चोटिल हुए इंग्लैंड के जूड बेलिंघम के स्थान पर खेल रहे ब्राहिम डियाज ने खेल के 48वें मिनट में गोल किया। लिपजिग के मिडफील्डर दानी ओल्मो ने कहा कि हम परिणाम से खुश नहीं हैं। हमारे गोल करने के कई अवसर थे।

नागल की नजरें ओलंपिक टिकट हासिल करने पर लगीं

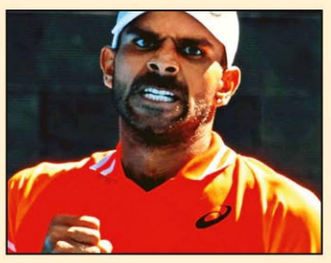

बेंगलुरू । चेन्नई ओपन में मिली जीत से उत्साहित टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल का लक्ष्य अब आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी रैंकिंग बेहतर करना है। सुमित अभी विश्व रैंकिंग में शीर्ष 100 में पहुंच गये हैं। वह 2019 में प्रजनेश गुणेश्वरन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। नागल ने कहा, ''हर टेनिस खिलाड़ी शीर्ष 100 में शामिल होने का सपना देखता है। मैंने काफी कम उम्र से शीर्ष 100 में शामिल होने का सपना देखा था और जब ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, ''हां, यह एक बड़ा क्षण था पर अब मैं एक नए टूर्नामेंट में खेल रहा हूं। आप जानते हैं कि टेनिस को सप्ताह दर सप्ताह लेने की जरूरत है। अब मैं बेंगलुरु में इस टूर्नामेंट में जीतने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं।'' नागल ने कहा, ''पर मेरा असली लक्ष्य ओलंपिक में जाना और अपने देश का प्रतिनिधित्व करना है। यह मेरे लक्ष्यों में से एक है और यह वास्तव में मुझे प्रेरित करता है। मैं ओलंपिक में खेलना और देश के लिए पदक जीतना चाहता हूं।'' गौरतब है कि इस साल 10 जून तक एटीपी (पुरुष) और डब्ल्यूटीए (महिला) रैंकिंग में शीर्ष 56 एकल खिलाड़ियों को जुलाई-अगस्त में होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए सीधे प्रवेश मिलेगा बशर्ते प्रति देश संख्या चार खिलाड़ियों से अधिक नहीं हो। वहीं जिन देशों के पास चार से कम स्वत: क्वालीफायर हैं उन्हें शीर्ष 56 के बाहर से प्रविष्टियों की अनुमति दी जाएगी।

एशिया टीम चैंपियनशिप में पीवी सिंधू की जीत के साथ वापसी, भारत ने चीन को 3-2 से हराया

नई दिल्ली ।
स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने चोट के कारण चार महीने बाद शानदार वापसी की है। भारत ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप (बीएटीसी) की महिला स्पर्धा में चीन की मजबूत टीम को 3-2 से हराया। सिंधू ने जीत के साथ शुरुआत की।

ग्रुप डब्ल्यू में सिर्फ दो टीम होने के कारण पहले मुकाबले से पूर्व ही भारत की नॉकआउट में जीत सुनिश्चित थी, लेकिन टीम ने शीर्ष वरीय चीन को हराकर शान से नॉकआउट में प्रवेश किया।

पिछले साल फ्रेंच ओपन के दौरान घुटने में लगी चोट के बाद से बाहर सिंधू ने अपने से बेहतर रैंकिंग वाली हेन युई को 40 मिनट में 21-17 21-15 से हराकर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता 28 साल की सिंधू की विश्व रैंकिंग 11 जबकि हेन युई की आठ है।

तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी हारी

तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी को इसके बाद ल्यु शेंग शु और टेन निंग की जोड़ी के खिलाफ 19-21 16-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी जबकि अस्मिता चालिहा भी दुनिया की नौवें नंबर की खिलाड़ी वैंग झी यी के खिलाफ 13-21 15-21 से हार गई जिससे तीन मैच के बाद भारत 1-2 से पिछड़ गया। त्रीशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने इसके बाद ली यी जिंग और लुओ शू मिन की जोड़ी को एक घंटे और नौ मिनट में 10-21 21-18 21-17 से हराकर भारत को बराबरी दिलाई।

अनमोल खरब ने वू लियो यू को हराया

निर्णायक मुकाबले में दुनिया की 472वें नंबर की अनमोल खरब ने दुनिया की 149वें नंबर की वू लियो यू को एक घंटे और 17 मिनट में 22-20 14-21 21-18 से हराकर भारत की जीत सुनिश्चित की। भारतीय पुरुष टीम ग्रुप ए लीग मैच में हांगकांग से भिड़ेगी।

कमिंस को कप्तान बनाने से सनराइजर्स को होगा फायदा : गावस्कर

मुम्बई ।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर के अनुसार सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के 2024 सत्र में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को कप्तान बनाकर बिलकुल सही कदम उठाया है। गावस्कर ने कहा कि कमिंस एक बेहतरीन गेंदबाज होने के साथ ही कुशल नेतृत्वकर्ता भी हैं। हैदराबाद ने पिछले साल दिसंबर में हुई नीलामी में कमिंस को 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा था। गावस्कर ने कहा कि कमिंस का कप्तान कौशल और ऑलरराउंडर होना अंतर पैदा करता है। इससे टीम की जीतने की संभावनाएं बढ़ती हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि कमिंस एक स्मार्ट खरीदारी थी, शायद थोड़ी अधिक महंगी।

स्मार्ट खरीदारी क्योंकि वह उनकी टीम में नेतृत्व का पहलू सामने लाएंगे, जिसकी पिछली बार सनराइजर्स टीम में कमी थी। इस पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, पिछली बार गेंदबाजी में महत्वपूर्ण मैचों में जो बदलावा देखे थे, वे फायदेमंद नहीं थे, और इससे ही टीम के हाथों से मैच निकल गया। अब पैट कमिंस के आने से मुझे भरोसा है कि टीम के जीतने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

कमिंस की बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता एक एक्स फैक्टर है। गावस्कर ने कहा कि आईपीएल 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से कमिंस ने 14 गेंदों में ही अर्धशतकीय पारी खेलकर दिखाया था कि वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। हैदराबाद ने कमिंस अलावा ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज ट्रैविस हेड को भी 6.80 करोड़ रुपए में खरीदा है। साथ ही कहा कि हेड भी अपने बल पर ही मैच का रुख बदल सकते हैं। गावस्कर ने कहा कि मयंक अग्रवाल या राहुल त्रिपाठी के साथ हेड की जोड़ी सही रहेगी।

एसए20 ने दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट का विकास किया है: ग्रीम स्मिथ

मुम्बई ।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और दक्षिण अफ्रीका 20 लीग के आयुक्त ग्रीम स्मिथ ने लीग की शुरुआत से अब तक की यात्रा की सराहना की और बताया कि कैसे एसए20 ने दक्षिण अफ्रीका में खेल को पुनर्जीवित किया है। एसए20 का सीज़न 2 हाल ही में संपन्न हुआ, जिसमें सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने दूसरी बार खिताब जीता। एसए20 की शानदार सफलता ने देश की क्रिकेट यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया। स्मिथ की भावनाएं गहराई से प्रतिबिंबित हुईं क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में देश में क्रिकेट के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार किया। ग्रीम स्मिथ ने कहा,मुझे लगता है कि हमें ईमानदार होना होगा, क्रिकेट कई वर्षों से दक्षिण अफ्रीका में अपना रास्ता खो चुका है, विभिन्न कारणों से, चाहे वह टीम का प्रदर्शन हो, चाहे वह क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका स्तर पर मुद्दे हों। और मुझे लगता है कि मेरे लिए यह पीछे की भावना को देखना बहुत अच्छा था, जब आप रग्बी और फुटबॉल के लोकप्रिय होने के बारे में सोचते हैं, जाहिर तौर पर वे राष्ट्रीय स्तर पर

लोकप्रिय हैं, लेकिन एक घरेलू आधारित टूर्नामेंट के लिए हम बोर्ड भर में संख्याएं बढ़ाने में सक्षम हैं और बहुत अच्छी तरह से प्रतिस्पर्धा करें, इसलिए हमने वास्तव में इसी अवधि में अन्य खेलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। तो यह बेहद सकारात्मक है और मेरे लिए दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट को फिर से मजबूत होते देखना, लोगों को बाहर आते देखना, युवाओं को खेलों के लिए आते देखना और दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट के खेल को वापस आते देखना, मुझे लगता है कि मेरे लिए यह रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण है। हमने ऐसा करने के लिए एसए20 की स्थापना की है और मुझे लगता है कि हम दक्षिण अफ्रीका में लोगों को फिर से खेल से प्यार दिलाने की यात्रा पर हैं। हालाँकि, एसए20 आशा की किरण बनकर उभरा, जिसने क्रिकेट की भावना को प्रवलित किया और घरेलू और वैश्विक स्तर पर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

मैराथन धावक केल्विन किप्टम की मौत: पुलिस ने चार लोगों को किया गिरफ्तार

नैरोबी।
केल्विन किप्टम की मौत के मामले में गिरफ्तारियां की गई हैं, क्योंकि उनके पिता सैमसन चेरुइयोट ने दावा किया था कि कार दुर्घटना से पहले चार अजनबी उनके घर पर मैराथन विश्व रिकॉर्डर की तलाश में आए थे। केन्याई पुलिस ने पुष्टि की कि चेरुइयोट द्वारा गहन जांच की मांग के बाद चार अज्ञात लोगों को हिरासत में लिया गया है। के24 टीवी ने कीयो साउथ सब काउंटी के कमांडेंट अब्दुल्लाही दाहिर के हवाले से कहा, आगे की जांच के लिए चारों को एल्गेयो माराक्वेट ले जाया गया। केन्याई अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, किप्टम टोयोटा प्रीमियो चला रहे थे। उनके साथ दो यात्री और सवार थे, जिसमें उनके कोच गेरवाइस और एक महिला थी जिनका नाम शेरोन कोस्गे बताया जा रहा है। शेरोन कोस्गे गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जबकि एथलीट और उनके कोच ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी जिसके बाद शवों को रेसकोर्स अस्पताल के मुर्दाघर में ले जाया गया। काउंटी कमांडर ने कहा, यह एक दुर्घटना थी,

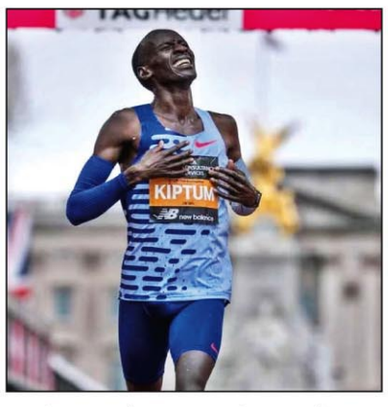

जिसमें विश्व मैराथन रिकॉर्ड धारक केल्विन किप्टम कार खुद ड्राइव कर रहे थे और उनके साथ अन्य लोग भी थे। किप्टम और हाकिज़िमाना की मौके पर ही मौत हो गई और शेरोन को एल्डोरेट के रेसकोर्स अस्पताल ले जाया गया। काउंटी कमांडर के अनुसार, किप्टम ने वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद कार सड़क से उतर गई और लगभग 60 मीटर दूर खाई में गिरने से पहले एक बड़े पेड़ से टकराई। किप्टम हाल के वर्षों में रोड रनिंग में उभरने वाली सबसे रोमांचक नई संभावनाओं में से एक थे। उन्होंने तब सुर्खियां बटोरीं जब उन्होंने दिसंबर 2022 में वालेंसिया में मैराथन की शुरुआत करते हुए 2:01:53 का समय लेकर जीत हासिल की। एक साल से भी कम समय के बाद अपनी तीसरी मैराथन में उन्होंने शिकागो में जीत हासिल करने के लिए 2:00:35 के साथ विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस प्रदर्शन के साथ वर्ष की शुरुआत में लंदन मैराथन में 2:01:25 के कोर्स रिकॉर्ड में उनकी जीत के साथ, उन्हें पुरुषों की आउट-ऑफ-स्टेडिया स्पर्धाओं के लिए 2023 विश्व एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया।

सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप में बिहार चैंपियन बना

अहमदाबाद। बिहार की सब-जूनियर लड़के और लड़कियों की टीम ने यहां आईआईटी-गांधीनगर में आयोजित सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप में लगातार तीसरी बार विजेता बनकर एक बार फिर अपना दबदबा कायम किया। सब-जूनियर ब्वॉयज ने एकतरफा मुकाबले में ओडिशा को 35-0 से हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। लड़कियों की टीम ने भी ओडिशा को 5-0 से हराया। यह बिहार राज्य के लिए तिहरापन पूरा करता है क्योंकि लड़के और लड़कियों दोनों की टीमें दो दिनों की प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहीं। इससे पहले प्रतियोगिता में बिहार की लड़कियों की टीम ने पहले सेमीफाइनल में महाराष्ट्र को 25-0 से और लड़कों ने राजस्थान को 5-0 से हराया। दूसरा सेमीफाइनल केरल और ओडिशा के बीच खेला गया, जिसमें ओडिशा के लड़के 5-0 के मामूली अंतर से शीर्ष पर रहे। लड़कियों का दूसरा सेमीफाइनल राजस्थान और ओडिशा के बीच खेला गया, जहां ओडिशा ने 5-0 के अंतिम स्कोर के साथ फाइनल में अपनी जगह बनाई। राजस्थान ने बालक वर्ग में केरल को 15-0 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि बालिका वर्ग में तीसरे/चौथे स्थान के मैच में महाराष्ट्र ने राजस्थान को 5-0 से हराया। यह टूर्नामेंट भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ (रग्बी इंडिया) द्वारा रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ गुजरात रग्बी के सहयोग से 2 दिनों तक आयोजित किया गया था, जिसमें अंडर14 लड़कियों की श्रेणी में कुल 24 टीमों और अंडर14 लड़कों की श्रेणी में 25 टीमों ने भाग लिया था।

चेहरे के दाग-धब्बों से छुटकारा दिलाता है अंजीर

ड्राइफ्रुट्स भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। अंजीर खाने के भी काफी फायदे हैं। आयुर्वेद के चिकित्सक डॉ. प्रसाद के मुताबिक अंजीर खाने से किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। नियमित रूप से अंजीर खाकर कब्ज की समस्या से राहत पाया जा सकता है। इसके अलावा रात को पानी में दो से तीन अंजीर भिगोकर रखें। इसे रोजाना सुबह उठकर खा लें। इससे कब्ज यानी हाज्मे से जुड़ी समस्या से निजात पाया जाता है।

अंजीर खाने के फायदे-

1-अंजीर का पेस्ट बनाकर भी अपने चेहरे पर लगा सकती हैं। इसे 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर लगाए रखें। सूखने के बाद चेहरा धो लें। इससे आप चेहरे के सभी दाग धब्बे निकल आते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे दूध में भिगोकर भी खा सकते हैं। इससे चेहरे के दानों या कील-मुंहासों से मुक्ति मिलती है।

2-अंजीर में फास्फोरस, विटामिन डी और कैल्शियम पाया जाता है। ये सभी तत्व आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। जिन महिलाओं की उम्र 50 पार कर चुकी है, उन्हें अक्सर ओस्टियोपोरोसिस और पीठ में दर्द की शिकायत होती हैं। ऐसी महिलाओं को निश्चित रूप से अंजीर को अपनी डायट चार्ट में शामिल करना चाहिए।

3-सूखे अंजीर में एन्टीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। प्राकृतिक अंजीर में सूखे अंजीर के तुलना में कम एन्टीऑक्सिडेंट्स के गुण होते हैं।

विरासत में मिला पैसा

बच्चे के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है

हर मां-बाप को अपने बच्चों से प्यार होता है। वे उनकी परवरिश का पूरा ख्याल रखते हैं। उनकी खुशी का ख्याल मरते दम तक होता है। वे इतनी संपत्ति छोड़कर जाना चाहते हैं कि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं हो। लेकिन हर शख्स इतना खुशकिस्मत नहीं होता। मतलब कुछ मां-बाप के पास बच्चों के नाम छोड़ने लायक कुछ बचता ही नहीं।

कुछ बच्चे (युवा, या अधेड़) ऐसे होते हैं कि विरासत उनकी कीमत घटा देती है, यानी सेल्फवर्थ को जीरो कर देती है। समाज उनकी हर कामयाबी को उनकी मेहनत नहीं बल्कि विरासत से जोड़कर देखने लगता है। इन सबके चलते उन्हें शर्म, अपराधबोध और दुविधा महसूस होने लगती है। वे खुद को अलग-थलग महसूस करने लगते हैं।

कई बार लोग जाने-अनजाने जलने लगते हैं और उनके प्रति व्यवहार में अक्सर जताने भी लगते हैं। कई बार बेवजह की यह जलन उनके प्रति एक घृणा का रूप ले लेती है। विरासत में बुजुर्गों से संपत्ति पाने वाला बेकसूर शख्स भी आम लोगों से कटा-कटा रहने लगता है। उसकी कोशिश होती है कि वह ऐसे लोगों के बीच उठे-बैठें, जिन्हें विरासत में मिली उनकी संपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता।

मुद्दा

विरासत में संपत्ति पानेवाले ऐसे शख्स के मन में क्या चलता रहता है, यह जानने के लिए बारबरा बॉलिन इनहेरिटेंस प्रोजेक्ट चलाती हैं और उनके इंटरव्यू छापती हैं। उनके हिसाब से पैरंट्स को चाहिए कि वे समय रहते बच्चों को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करा दें। यह काम कई चरणों में किया जा सकता है। जैसे पहला चरण, यह हो सकता है कि पेरेंट्स शुरुआत से ही बच्चों को जताना शुरू कर दें कि उन्हें क्या मिलने वाला है। उनकी प्राथमिकताओं को समझें और उनको यह समझने में मदद करें कि विरासत में मिली संपत्ति का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। पैसों को किसी ट्रस्ट में डालने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, अगर मकसद एक ना हो।

अगर बच्चा चाहता है कि वह कुछ संपत्ति समाज के साथ शेयर करे या अच्छे काम के लिए दान करे तो उनको इसके लिए तैयार करना चाहिए। स्टडी से पता चला है कि लोग विरासत में मिली संपत्ति अपनी प्रकृति के हिसाब से भौतिक सुख साधन, निवेश, सामाजिक कार्य वगैरह में लगाते हैं। उनको उसी हिसाब से तैयार किया जाना चाहिए। दूसरा चरण, मकसद तय करने में उनकी मदद की जाए। अगर बच्चे का सपना दूरदराज के गांव में स्कूल चलाना है तो शहर में 2BHK में पैसा फंसाने का कोई मतलब नहीं बनता। पैरंट्स बच्चे का यह सपना पूरा करने के लिए अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उसकी बेहतर पढ़ाई लिखाई पर खर्च कर सकते हैं। ऐसे काम की लिस्ट बनाने में बच्चे की मदद करना चाहिए जो उसका जीवन बेहतर बनाए।

तीसरा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे वित्तीय तौर पर साक्षर बनें। विरासत में अपार संपत्ति पाने वालों के लिए कुछ ऑनलाइन स्कूल भी हैं। वहां वित्तीय फैसले लेने, उसके नफा नुकसान, कॉस्ट, फीस, टैक्सेशन कंप्लायंस वगैरह के बारे में बताया जाता है। बच्चा आगे चलकर जटिल कार्यों के लिए पेशेवर की मदद ले सकता है लेकिन अपनी जरूरत को समझने के लिए वित्तीय रूप से साक्षर होना भी जरूरी है।

चौथा, जब विरासत में संपत्ति मिलती है तो दोस्तों रिश्तेदारों का संपर्क बढ़ जाता है। इनमें चाटुकारों, साजिश करनेवालों, बिना ब्याज उधार मांगने वाले अच्छी खासी की तादाद होती है। उधार लेने वालों में भी कई ऐसे होते हैं जो यह मान बैठे होते हैं कि वह कौन-सी अपनी कमाई दे रहा है। ऐसे में पैरंट्स को चाहिए कि वे बच्चों को कुछ रकम देकर भूल जाना भी सिखाएं।

ये सपरफूड भी बढ़ा सकते है कद

ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके माता-पिता छोटे कद के हैं तो आप पर भी उसका असर पड़ता है और आप भी छोटे रह जाते हैं। इसके अलावा लोग ये भी सोच रखते हैं कि किशोरावस्था के बाद लंबाई बढ़ना नामुमकिन है । लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप लंबा होना चाहते हैं तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको बस अपने खान-पान पर ध्यान देने की जरूरत है।

शलजम : शलजम में लंबाई बढ़ाने वाले हार्मोन्स होते हैं। नियमित रूप से इसे खाने से आपकी लंबाई बढ़ सकती है। इसके लिए आप इसकी सब्जी बनाकर या इसका जूस पी सकते हैं। कुछ ही महिनो में आपकी कुछ इंच लंबाई बढ़ जाएगी।

फलियां : फलियां यानी बींस में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। रोज इसे खाने से ग्रोथ हार्मोन पर प्रभाव पड़ता है।

भिंडी से भी बढ़ाई जा सकती है लंबाई

मटर

शायद जानकर हैरानी हो लेकिन मटर के दानों में भी लंबाई का राज छुपा है। रोजाना भोजन में मटर खाने से असर दिखेगा।

भिंडी

ज्यादातर लोग भिंडी खाना पसंद करते हैं । लेकिन इसके फायदों से अंजान हैं। इसकी सब्जी खाने से लंबाई के हार्मोन फंक्शन करने लगते हैं। जिससे आपकी लंबाई बढ़ती है।

पालक

जिस तरह पालक सेहत के लिए फायदेमंद है। उसी तरह लंबाई बढ़ाने के लिए भी आप इसे ट्राई कर सकते है। इसे सब्जी या जूस के रूप में लेने से लंबाई में फर्क दिखेगा।

लैपटाप की बैटरी लाइफ को बढ़ाने के ये हैं कुछ आसान उपाय

लैपटाप हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है. लैपटाप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफी आसान होता है. इसके जरिए आप कहीं भी बैठकर अपने सारे काम आसानी से कर सकते हैं. ज्यादातर कंपनियां दावा करती हैं कि उनके लैपटाप 4 से 6 घंटे की बैटरी लाइफ देंगे. लेकिन वास्तव में, लैपटाप का बैकअप टाइम पूरी तरह से आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है. नया लैपटाप खरीदने के बाद एक बार चार्ज करने पर वह 2-3 घंटे काम करता है. लेकिन 6 से 12 महीनों के बाद ही इन लैपटाप की बैटरी लाइफ कम हो जाती हैं, और ये 30 मिनट की ही बैटरी लाइफ देते हैं. लैपटाप का बैकअप टाइम पूरी तरह से आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है.आज हम आपको आपके लैपटाप की बैटरी लाइफ को बढ़ाने के कुछ आसान उपाय बताएंगे.

बैटरी बैकअप कम होने के कारण

लैपटाप की बैटरी 1-2 घंटे में चार्ज नहीं हो रही हैं तो जांच लें कि कहीं बैटरी ओवरहीट तो नहीं हो रही है. अगर ऐसा है तो ओवरहीट होने की समस्या को नजरअंदाज न करें क्योंकि यह मुख्य कारण होता है आपके डिवाइस की बैटरी लाइफ के कम होने का.

अगर आपके लैपटाप की बैटरी ज्यादा हिट हो रही हैं तो उसे तुरंत लैपटाप से निकाल के ठंडे स्थान पर रखें. बैटरी का रोज हिट होना सही नहीं है, हो सकता है कि आपकी बैटरी या चार्जर खराब हो.

लैपटाप को ओवरचार्ज करना भी बैटरी के लाइफ को कम कर देता है. जैसे-जैसे इसकी बैटरी पुरानी होती जाती है, बार-बार पावर प्लग इस्तेमाल करने की जरूरत भी बढ़ती जाती है.बैटरी की उम्र को ध्यान में रखते हुए लैपटाप को अपग्रेड करने से बेहतर बैटरी बदलना होता है.

तापमान का रखें ध्यान

ज्यादा तापमान और बढ़ती उम्र धीरे-धीरे बैटरी की परफार्मेंस को कम कर देते हैं. कम तापमान (30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न हो) में डिवाइस का इस्तेमाल करने से उसकी लाइफ साइकल बेहतर होगी. आप अपने डिवाइस को गर्मी से बचाने की कोशिश करें. स्मार्टफोन के ज्यादा गर्म होने की समस्या से परेशान होना वाजिब है, लैपटाप में इस बात का ध्यान रखें कि आप कूलिंग पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि सीपीयू वेंट से गर्म हवा आसानी से निकल जाए. धूल के कारण अक्सर लैपटाप का वेंट बंद होने लगता है जिस कारण से उसमें बने पंखों को ज्यादा काम करना पड़ता है. इसलिए सफाई रखें, खासकर धूल को ज़रूर हटाएं.

मुफ्त ऐप से बचें

विज्ञापन के साथ आने वाले ऐप्स आपके डिवाइस की बैटरी लाइफ औसतन 2.5 से 2.1 घंटे तक कम कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सभी फ्री ऐप्स आपकी बैटरी पर असर डालते हैं, लेकिन अगर आपको उस पर कोई विज्ञापन नजर आए तो समझ लीजिए कि यह बैंडविथ और प्रोसेसर पर असर डालेगा ही. अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वाई-फाई का कनेक्शन औफ कर दें.

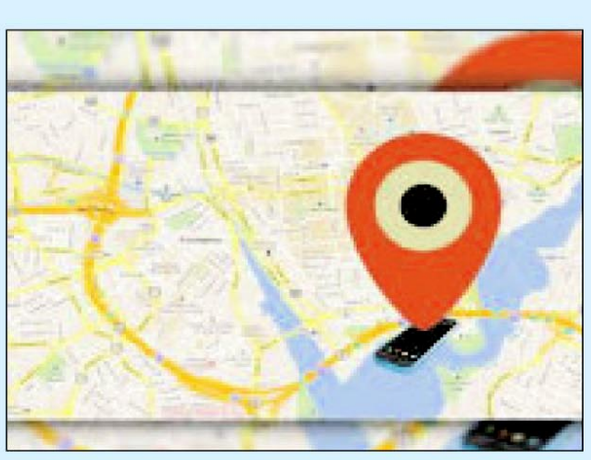

लोकेशन ट्रैकिंग बंद कर दें

हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक ऐप डिवाइस की बैटरी को जल्दी खत्म करता है क्योंकि यह बार-बार जीपीएस मौड्यूल का इस्तेमाल करके यूजर की लोकेशन जानता रहता है. ऐसे में जिन ऐप को आपके लोकेशन की जरूरत नहीं है, उनके लोकेशन ट्रैकिंग को औफ कर देने से जरूर मदद मिलेगी.

पूरी तरह चार्ज से बेहतर है थोड़ा-थोड़ा चार्ज करें

बैटरी को 100 फीसदी से सीधे ले जाकर शून्य पर खत्म करने से बेहतर है कि आप इसे 50 फीसदी तक ही डिस्चार्ज होने दें. 30 से 80 फीसदी के बीच का क्रम बनाए रखें. ऐसा करने से आपके बैटरी की लाइफ तीन गुना बढ़ जाएगी. बैटरी को कई साल तक इस्तेमाल करने योग्य बनाने कि लिए लेनेवो का सुझाव है कि आप चार्जिंग का पैटर्न 40 फीसदी से शुरुआत और 50 फीसदी पर बंद, तय कर दें.

डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम रखें

यह सुझाव लैपटाप और मोबाइल डिवाइस पर लागू होता है. डिवाइस के इनएक्टिव रहने पर आपका डिस्प्ले कितनी देर तक आन रहे, यह कम करके और डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम करके भी आप थोड़ी बैटरी बचा सकते हैं.

चार्ज करते वक्त या वाई-फाई पर ऐप अपडेट करें

आमतौर पर कोई भी एक्शन जिससे प्रोसेसर या बैंडविथ पर दबाव पड़ता है, वह ज्यादा ही सीपीयू पावर लेगा. ऐसे मे बेहतर यह होगा कि एक्शन आम तौर पर स्थिर रहे और आप मोबाइल डेटा इंटरनेट के बजाय वाई-फाई का इस्तेमाल करे. आप अपने ऐप्स अपडेट को वाई-फाई पर शेड्यूल करें. अगर आपके डिवाइस में विकल्प मौजूद है तो सिर्फ चार्ज होते वक्त इसे शेड्यूल कर बैटरी लाइफ को बढा सकते है.

फ्लाइट मोड का इस्तेमाल करें

अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां कोई नेटवर्क नहीं है तो बेहतर होगा कि आप फोन में एयरप्लेन मोड (फ्लाइट मोड) को आन कर दें क्योंकि आपका फोन ऐसी जगहों पर बार-बार नेटवर्क तलाश करेगा जिसका असर बैटरी लाइफ पर पड़ेगा.

लैपटाप से एक्सटर्नल ड्राइव को अलग रखें

अक्सर देखने में आता है कि लैपटाप यूजर्स स्क डिवाइसेस जैसे पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को लगातार अटैच करते है और अटैच ही रखते हैं. ये डिवाइसेस बैटरी के पावर को लगातार पावर को कम करती हैं. ऐसे में जब भी एक्सटर्नल डिवाइसेस का काम पूरा हो जाए तो उन्हें फौरन लैपटाप से रिमूव कर दें.

इन सुझावों का इस्तेमाल कर आप अपने फोन को पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर बैटरी लाइफ दे सकते है.

ब्रेक भी जरूरी

यदि आप सारा दिन कम्प्यूटर के सामने बैठकर लगातार काम करते हैं, या किसी कॉल सेंटर में पूरा दिन फोन पर बात करते हैं, तो जरा ब्रेक लीजिये। लगातार बैठकर काम करते रहना, शरीर पर भारी पड़ सकता है। कम्प्यूटर के अधिकाधिक इस्तेमाल से कलाइयों और हाथों पर दबाव के कारण 'कारपल टनल सिंड्रोम' बीमारी ब ?ती जा रही है। इसमें शुरुआत में दर्द होता है, हाथों में झनझनाहट होती है और हाथ सुन्न लगते हैं। उंगलियों को मोड़ने या मुट्ठी बंद करने में परेशानी होती है। वहीं, बैठने का तरीका यदि सही नहीं है तो कंधे, गर्दन और पीठ को नुकसान हो सकता है। लंबे समय तक कम्प्यूटर के सामने बैठे रहने से आंखों के स्नायुओं में जल्दी थकान होने लगती है। लगातार स्क्रीन की ओर देखते रहने से पलकों का झपकना भी कम हो जाता है। इसके चलते नजर कमजोर होना, सिर दर्द और चक्कर जैसी समस्या घेर सकती है। बिना किसी से बातचीत किए लगातार कई घंटों तक कम्प्यूटर पर काम करते रहने पर थकान और तनाव के कारण 'एपैथी सिंड्रोम' होने का डर है। इसमें भूख न लगना, चिड़चिड़ापन और नींद न आने की दिक्कतें घेर लेती हैं।

काम करते समय सहज रहना आवश्यक है। इस दिशा में पहला कदम है ऑफिस के 5 मुख्य नियमों को जानना।

1. शरीर को ढीला छोड़कर धीरे-धीरे लंबी सांस लीजिये।
2. कार्य को सरल बनाएं। एक समय में एक ही काम करें।
3. काम शान्तिपूर्वक और एकाग्र हो कर करें।
4. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनावग्रस्त न हों।
5. आवश्यकतानुसार बीच-बीच में विश्राम करें।

छोटे कदम, बड़ी राहत

» देर तक ऑफिस में काम करने के कारण हो सकता है शारीरिक व्यायाम के लिए समय ही न बचता हो। ऐसे में शारीरिक व्यायाम के अन्य विकल्प खोजने आवश्यक हैं।

» किसी प्रोजेक्ट पर सहयोगी के साथ विचार-विमर्श करना है, तो यह काम बैठकर करने के बजाय, चलते हुए कर सकते हैं।

» टेलीफोन पर खड़े होकर बात कीजिये।

» ऑफिस में किसी से बात करनी हो तो फोन के बजाय उसके पास जाकर बात करें।

» लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें।

» बिजनेस ट्रिप पर हों तो ऐसे होटल में रुकें जहां स्विमिंग पूल अथवा फिटनेस सेंटर हो।

» एयरपोर्ट पर फ्लाइट की प्रतीक्षा करते समय बैठिए नहीं, टहलते रहिए।

» अपने सूटकेस में कूदने की रस्सी रखें। होटल में समय मिलने पर अपने कमरे में रस्सी कूदिये।

» परोपकार कार्यों के लिए थोड़ा समय निकालिये।

» कार्यस्थल के समीप किसी फिटनेस सेंटर के सदस्य बन जाएं। काम से पहले, बाद में वहां व्यायाम कर सकते हैं।

» बिजनेस कैलेंडर में व्यायाम का समय निर्धारित कर लें। महत्वपूर्ण कार्य की तरह उसको भी प्राथमिकता दें।

» बस से ऑफिस जाते समय अथवा आते समय थोड़ा पहले उतर जाएं और बाकी का रास्ता पैदल पार करें।

» लंच ब्रेक अथवा समय मिलने पर अपने ऑफिस के इर्द-गिर्द ही चक्कर काट लें। थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं।

» इन सहज-सरल नियमों का अनुपालन करके हम तनावमुक्त रहकर पूरा दिन आनन्दपूर्वक व स्फूर्ति के साथ व्यतीत कर सकते हैं। इससे मस्तिष्क की सृजनशीलता बढ़ती है।

मुद्रक एवं प्रकाशक राकेश शर्मा द्वारा अजय त्यागी के लिए ईको प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट एवं पीएस : गड़चुक, कटाबाड़ी मस्जिद के पास, कामरूप (मेट्रो), गुवाहाटी-35 से मुद्रित एवं **गुड लक पब्लिकेशंस, हाउस नं. 30, डी. नेउग पथ, डोना प्लैनेट के नजदीक, एबीसी, जीएस रोड गुवाहाटी-5 से प्रकाशित।**
संपादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 94350-14771, 97070-14771 ● **कार्यकारी संपादक : डॉ. आसमां बेगम ● फोन : 0361-2960054 (संपादकीय)** e-mail : viksitbharatsamacharghy@gmail.com, **(सभी विवाद सिर्फ गुवाहाटी न्याय क्षेत्र के अधीन)**